निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र विचार व अपराध निरोधक

दिल्ली क्राईम व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा

DELHI CRIME WA BHRASHTACHAR VIRODHI MORCHA

RNI:DELHIN/2005/15378
WWW.DELHICRIMEPRESS.IN

Delhi Journalism & Investigation Research Institute — Regd. By Govt Of NCT Delhi — दिल्ली पत्रकारिता एवं अन्वेषण अनुसंधान संस्थान

RNI No. DELHIN/2005/15378 ● DCP Lic. No. F-2(D-9)PRESS/2005 ● वर्ष-22 ● 01 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक ● अंक -1, 2 ● पृष्ठ-8 ● मूल्य-10रू

हरियाणा से आए हुए कलम के सिपाहीयो का हुआ शिव चौक पर स्वागत

डाडा जलालपुर में जल भराव की समस्या से लोग परेशान!

दिल्ली में बढ़ती ठंड और प्रदूषण ने बढ़ाई परेशानी

सबलपुर बीतरा के पूर्व छात्र दीपांशु राजपूत ने ठंड से राहत दिलाई: नूतन इंटर कॉलेज तिसोतरा के गरीब बच्चों को बांटी जर्सी व जूते रिपोर्ट : लव कुमार

विश्व हिंदू महासंघ प्रिंट मीडिया से प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष बने सूरज सोनी

मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में रेड क्रॉस द्वारा 60 कंबलों का वितरण, तीमारदारों को मिली बड़ी राहत

प्रधानमंत्री ने पारंपरिक चिकित्सा को उसके हक की मान्यता दिलाने का किया आह्वान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पारंपरिक चिकित्सा को उसके हक की मान्यता दिलाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विज्ञान के माध्यम से विश्वास जीतना होगा और इसकी पहुंच का विस्तार करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यहां के भारत मंडपम में आयोजित द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह भारत की पारंपरिक औषधीय विरासत की वैश्विक महत्ता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा को लम्बे समय तक केवल स्वास्थ्य और जीवनशैली संबंधी देखभाल तक ही सीमित रखा गया। अब यह धारणा तेजी से बदल रही है। भारत इस सोच से आगे बढ़ रहा है कि पारंपरिक चिकित्सा गंभीर परिस्थितियों में भी प्रभावी भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक चिकित्सा पर विश्वास से जुड़ी कमी को दूर करने के लिए भारत के निरंतर प्रयासों का उल्लेख करते हुए अश्वगंधा का उदाहरण सामने रखा। उन्होंने कहा कि सदियों से उपयोग में रही अश्वगंधा की कोविड-19 के दौरान वैश्विक मांग बढ़ी। भारत शोध और साक्ष्य-आधारित प्रमाणीकरण के जरिए इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रामाणिक रूप से स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक चिकित्सा को मजबूत करने के उपाय बताये और कहा कि इसमें पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान को सुदृढ़ करना, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को विस्तार देना और विश्वसनीय नियामक ढांचा तैयार करना शामिल है। प्रधानमंत्री ने आने वाले समय को मानव शरीर के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां पैदा करने वाले बताया और कहा कि परंपरागत स्वास्थ्य देखभाल में हमें वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी फोकस करना है। उन्होंने कहा कि शारीरिक श्रम के बिना संसाधनों और

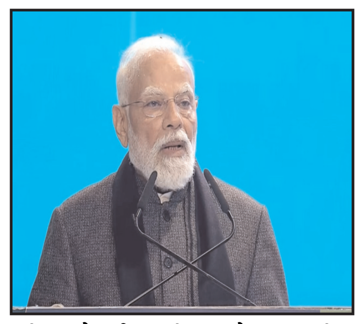

सुविधाओं की सहूलियत से अप्रत्याशित चुनौतियां पैदा होने जा रही हैं। हमारी साझा जिम्मेदारी आने वाले भविष्य को लेकर भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद में संतुलन को स्वास्थ्य का मूल आधार माना गया है और जिसके शरीर में यह संतुलन बना रहता है, वही स्वस्थ होता है। बदलती जीवनशैली, बढ़ते तनाव और पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण संतुलन की यह अवधारणा वैश्विक महत्व की बन गई है। ह्यरिस्टोरिंग बेलेंसह्ल अब एक गंभीर वैश्विक आवश्यकता है, जिसे संबोधित करने के लिए तेज और ठोस कदम जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि भारत के प्रयासों और 175 से ज्यादा देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को योग दिवस घोषित किया गया था। बीते वर्षों में हमने योग को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचते देखा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री दिल्ली में नए डब्ल्यूएचओ-दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने इसे भारत की ओर से एक विनम्र उपहार बताया। इसमें डब्ल्यूएचओ भारत का कंट्री ऑफिस भी होगा। प्रधानमंत्री ने आयुष क्षेत्र के लिए एक मास्टर डिजिटल पोर्टल, माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल (एमएआईएसपी) सहित कई महत्वपूर्ण आयुष पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने आयुष मार्क का भी अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने योग प्रशिक्षण पर डब्ल्यूएचओ की तकनीकी रिपोर्ट और ह्यफ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीचः 11 इयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आयुषह्ल नामक पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने वर्ष 2021-2025 के लिए योग के संवर्धन एवं विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक चिकित्सा खोज अंतरिक्ष का भी दौरा किया। यह प्रदर्शनी भारत और विश्व भर की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान प्रणालियों की विविधता, गहराई और समकालीन प्रासंगिकता को प्रदर्शित करती है। डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से संयुक्त रूप से 17 से 19 दिसंबर तक भारत मंडपम में आयोजित शिखर सम्मेलन का विषय ह्यसंतुलन की बहालीः स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और व्यवहारह्ल रहा। सम्मेलन में वैश्विक नेताओं, नीति निमार्ताओं, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, स्वदेशी ज्ञान धारकों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के बीच न्यायसंगत, टिकाऊ और साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ावा देने पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

कक्षा 12 के युवा एथलीट वंश कथूरिया ने 4 से 7 दिसंबर 2025 को वर्ल्ड चैंपियन शिप इलेवन रशिया में पावरलिफ्टिंग गेम में भारत और अपने स्कूल का नाम गौरवान्वित किया, बने विश्व के रिकॉर्ड धारक

रूस मास्को में अयोजित विश्व चैंपियनशिप में भारतीय दल के युवा एथलीट वंश कथूरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 02 स्वर्ण या एक रजत पदक जीता। इतना ही नहीं वंश कथूरिया ने पावरलिफ्टिंग गेम खेलते हुए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोडा और अपनी वेट कैटेगरी में 492.5 KG वजन उठा कर रिकॉर्ड होल्डर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब हासिल किया।वंश कथूरिया ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि अपनी मजबूत इच्छाशक्ति और अथक प्रयास के दम पर हासिल की। उनकी जीत ने भारत को और अपने स्कूल को गौरवान्वित महसूस कराया है और ये सबित कर दिया है कि भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी से कम नहीं है। वंश की इस ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें, उनके पूज्य पिताजी श्री गगन कुमार जी, पूज्य दादा जी एवं दादी जी को, उनके आदर्श गुरु जी श्री विक्रम फोगाट जी तथा उनके प्रधानचार्य जी (इंदर मलिक सर जी), लवली पब्लिक स्कूल, न्यू लायल पुर, कृष्णा नगर दिल्ली-110051 और उनकी समस्त टीचर्स को हार्दिक शुभकामनाये मेडल और रिकॉर्ड की जानकारी :- स्वर्ण पदक 02 रजत पदक 01 कुल वजन कुल 492.5 किलोग्राम अन्य उपलब्धि 492.5 किलोग्राम कुल वजन के साथ एक ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड। वंश कथूरिया ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और 492.5 किलोग्राम के टोटल से भारत का झंडा विश्व पटल पर ऊंचा किया है। ये ऐसिहासिक उपलब्धि उसके विश्वास,उनके आदर्श गुरु जी श्री विक्रम फोगाट जी, भगवान का आशीर्वाद और सबकी दुआ और उनके पूज्य पिताजी के संघर्ष की वजह से है.

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए लगेंगे 11 लाख पौधे : भूपेन्द्र यादव

नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 तक क्षेत्र में 11 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इससे वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा। भूपेन्द्र यादव ने यह बात दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण पर आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा में कही। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ यह उनकी चौथी समीक्षा बैठक थी। इसका उद्देश्य "प्रदूषण मुक्त एनसीआर" के लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रशासन को अधिक सक्रिय, संगठित और जवाबदेह बनाना है। यादव ने कहा कि जनवरी 2026 से सभी कार्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हर महीने सीधे मंत्री स्तर पर की जाएगी। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने सभी शहरों की प्रदूषण योजनाओं को एकीकृत करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि आम जनता को बेवजह परेशानी ना हो। इसके बाद सुधारात्मक कार्रवाई की समीक्षा आगामी 15 दिनों में दोबारा की जाएगी। इस बैठक में कंपनियों को कर्मचारियों के लिए ईवी या सीएनजी बसें चलाने, ऑफिस और मॉल के समय में बदलाव, सड़कों से अतिक्रमण 10 दिनों में हटाने और जागरूक संबंधी विशेष अभियान चलाने जैसे अन्य सुधारात्मक सुझाव दिए गए।

सबलपुर बीतरा की जर्जर सड़कः दिल्ली क्राइम प्रेस की खबर से खुला मामला, गड्ढों से त्रस्त ग्रामीणों को जल्द मिलेगी राहत, जिला पंचायत बैठक में प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद

नजीबाबाद (बिजनौर): ग्राम सबलपुर बीतरा को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली लगभग 700 मीटर लंबी सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो जाने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए इस स्ताव तैयार कर लिया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी बैठक में रखा जाएगा। बैठक में स्वीकृति मिलते ही मरम्मत कार्य तत्काल शुरू कर दिया जाएगा। जिला पंचायत के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "हमने ग्रामीण की शिकायतसड़क का उपयोग करना जोखिम भरा हो गया है। बारिश के दिनों में तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं, जब कीचड़ और पानी से सड़क पूरी तरह दलदल में तब्दील हो जाती है। इस समस्या को लेकर ग्रामीण लव कुमार पुत्र

ओम प्रकाश ने उत्तर प्रदेश सरकार के एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी, जिसका संदर्भ संख्या 40013425031094 है। शिकायत के बाद जिला पंचायत विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क का मुआयना किया और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मरम्मत के लिए त्वरित कार्रवाई की है। सड़क की मरम्मत के लिए आवश्यक बजट और तकनीकी अनुमोदन का प्रस्ताव तैयार है। उम्मीद है कि अगली बैठक में इसे मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद कार्य एजेंसी को सौंपकर मरम्मत शुरू हो जाएगी।" ग्रामीण लव कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में खुशी जाहिर करते हुए कहा, "लंबे समय से हम इस सड़क की बदहाली से जूझ रहे थे। गड्ढों के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मैंने IGRS पर शिकायत की तो विभाग ने फौरन एक्शन लिया। मौका मुआयना हुआ और अब प्रस्ताव तैयार है। हमारी आवाज सुनी गई, बस अब मीटिंग का इंतजार है। मरम्मत हो जाने से गांव के सैकड़ों लोगों को राहत मिलेगी। गांव के अन्य निवासियों ने भी प्रशासन के इस कदम की सराहना की है। एक बुजुर्ग ग्रामीण रमेश सिंह ने कहा, "यह सड़क गांव की लाइफलाइन है। इसके खराब होने से बाजार जाना, खेती का सामान लाना-ले जाना सब मुश्किल हो गया था। उम्मीद है जल्द नई सड़क बनकर तैयार हो जाएगी।" जिला पंचायत की बैठक जल्द आयोजित होने की संभावना है, जिसमें इस प्रस्ताव सहित क्षेत्र की अन्य विकास योजनाओं पर चर्चा होगी। ग्रामीणों की मानें तो मरम्मत कार्य पूरा होने से न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि गांव का समग्र विकास भी गति पकड़ेगा।

संवाददाता, लव कुमार, सबलपुर बीतरा, नजीबाबाद (बिजनौर)

सम्पादकीय

मनरेगा से वीबी-जी राम जी

भारतीय लोकतंत्र में कुछ कानून केवल विधायी दस्तावेज नहीं होते, बल्कि वे सामाजिक अनुबंध का रूप ले लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम,यानी मनरेगा,ऐसा ही एक कानून था। वर्ष 2005 में पारित इस अधिनियम ने पहली बार ग्रामीण भारत के नागरिकों को काम का कानूनी अधिकार दिया। अब, ठीक बीस वर्ष बाद, लोकसभा में भारी विरोध,हंगामे और विपक्षी प्रदर्शन के बीच विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) संक्षेप में वीबी-जी राम जी विधेयक संसद से पारित हो चुका है। संसद के शीतकालीन सत्र में सता पक्ष व विपक्ष ना केवल नोक - झोक चली बल्कि लोकतंत्र मंदिर एक बार रणक्षेत्र में बदल गया। संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में जनता के हितो पर राष्ट्र निर्माण व विकाश के मुद्दे पर बहस होनी थी, वहाँ मोदी सरकार अपने कई विधयेक संसोधन बिल को विपक्ष को दर किनार कर शोर गुल में पास किया है। इन विधयेक में मनरेगा बिल में संशोधन फिर इसे अधिकार से मिशन में स्थानांतरित किया गया है। जिस मनरेगा से वीबी-जी राम जी और ग्रामीण भारत के भविष्य पर मंडराता कई सवाल खड़े हो गए है। भारतीय लोकतंत्र में कुछ कानून केवल विधायी दस्तावेज नहीं होते, बल्कि वे सामाजिक अनुबंध का रूप ले लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी मनरेगा,ऐसा ही एक कानून था।वर्ष 2005 में पारित इस अधिनियम ने पहली बार ग्रामीण भारत के नागरिकों को काम का कानूनी अधिकार दिया। अब, ठीक बीस वर्ष बाद, लोकसभा में भारी विरोध, हंगामे और विपक्षी प्रदर्शन के बीच विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)–संक्षेप में वीबी-जी राम जी–विधेयक संसद से पारित हो चुका है। केन्द्र की सरकार इसे सुधार और विस्तार बता रही है,जबकि विपक्ष और नागरिक समाज इसे अधिकारों के क्षरण के रूप में देख रहे हैं। इस बहस को समझने के लिए भावनाओं से अधिक जरूरी है– डाट, विलेषण व प्रभाव। मनरेगा लागू होने के बाद से लेकर अब तक,यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो दशकों में मनरेगा के तहत हर वर्ष औसतन 5 से 6 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला। सन 2013-14 से 2022-23 के बीच,हर साल औसतन 250 से 300 करोड़ मानव-दिवस का सृजन हुआ। कोविड-19 महामारी के दौरान, वर्ष 2020-21 में यह आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा,जब लगभग 389 करोड़ मानव-दिवस का सृजन हुआ और करीब 7.6 करोड़ परिवारों ने इस योजना के तहत काम पाया। यह केवल एक संख्या नहीं थी,बल्कि उस समय करोड़ों परिवारों के लिए जीवनरेखा थी, जब शहरों से लौटे प्रवासी मजदूरों के पास कोई विकल्प नहीं था। मनरेगा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि यह योजना नहीं, बल्कि कानून था। यदि किसी ग्रामीण परिवार को 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता था, तो राज्य सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की विभिन्न रिपोर्टों में यह स्पष्ट किया गया है कि इस कानूनी बाध्यता के कारण ही राज्यों और केंद्र पर काम उपलब्ध कराने का दबाव बना रहा। यही वजह थी कि 2006 से 2023 के बीच मनरेगा पर केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर लगभग 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए। केवल 2023-24 के बजट में ही मनरेगा के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।अब सरकार जिस नए कानून को लाई है, वह इस अधिकार-आधारित ढांचे को मिशन आधारित स्वरूप में बदल देता है। वीबी-जी राम जी विधेयक में यह दावा किया गया है कि ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन तक रोजगार मिलेगा, जो मनरेगा के 100 दिन की तुलना में अधिक है। लेकिन यहां सवाल संख्या का नहीं, गारंटी का है। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार कानूनी अधिकार था, जबकि नए कानून में 125 दिन प्रशासनिक विवेक पर निर्भर होंगे। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जब रोजगार की गारंटी कानून से हटकर मिशन बन जाती है, तो उसका क्रियान्वयन बजट, प्राथमिकता और राजनीतिक इच्छा पर निर्भर हो जाता है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार,नए विधेयक में केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह यह तय करे कि किन क्षेत्रों में काम होगा, किस तरह के काम होंगे और किन परिस्थितियों में योजना को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। – नरेंद्र कुमार

उत्तर भारत - कोहरे के कोहराम से फना होती जिंदगियां!

लेखक - मनोज कुमार अग्रवाल

उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान कोहरा इतना घना हो जाता है कि कुछ मीटर आगे देख पाना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे हालात में थोड़ी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है. ऐसे में अगर छोटी-छोटी सावधानी पर ध्यान दिया जाए तो हादसों को रोका जा सकता है.सबसे भयावह दुर्घटना मथुरा के निकट, मंगलवार तड़के घने कोहरे के चलते कई वाहनों के आपस में टकराने से तेरह लोग जिंदा जल गए। यमुना एक्सप्रेसवे पर 16 दिसंबर को मथुरा के पास कोहरे के कारण सुबह करीब साढ़े तीन बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 8 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई. इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 70 से अधिक लोग घायल हो गए. इस हादसे से ठीक दो दिन पहले भी ऐसा ही एक हादसा हुआ. विजिबिलिटी कम होने के कारण यूपी-हरियाणा में एक के बाद एक कई हादसे हुए, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई. इन सभी हादसे की वजह कम विजिबिलिटी बताई जा रही है। मरने वाले निर्दोष लोग अपने-अपने जरूरी कामों के लिए जल्दी पहुंचने की चाहत में रात के सफर पर निकले थे। लेकिन हालात उन्हें मौत के मुंह में ले गया। बीते मंगलवार को अमंगल का यह कोहरे के कहर का सिलसिला यूपी हरियाणा पंजाब हिमाचल तक चला, और कितने ही जीवन लीला गया। पंजाब में जहां सुबह घने कोहरे के चलते पांच लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई। बरनाला व तपामंडी में हुए दो सड़क हादसों में एक ही परिवार के तीन लोगों समेत पांच लोगों की मौत हुई। वजह वही, घने कोहरे के चलते दृश्यता में कमी और स्थिति का आकलन न कर पाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। वहीं तपामंडी के व्यापारी की पत्नी व बेटी की मौत रास्ते में खड़े ट्रक से उनकी कार के टकराने से हुई। इससे पहले रविवार सुबह कोहरे के कोहराम से 66 वाहनों के टकराने से एक छात्रा समेत चार लोगों की मौत हरियाणा में भी हुई। चरखी दादरी में एक स्कूल बस व रोडवेज की बस की आमने-सामने की टक्कर में एक ग्यारहवीं की छात्रा की मौत हो गई और तीस से अधिक छात्राएं व शिक्षक, बस चालक समेत घायल हो गए। वहीं तेज रफ्तार वाले नेशनल हाईवे पर एक के बाद एक, अनेक वाहन दृश्यता की कमी के चलते दुर्घटनाग्रस्त हुए निश्चय ही निर्दोष लोगों का यूं असमय काल-कवलित होना बेहद दुखद ही है। सवाल फिर वही है आखिर कब तक कोहरा कहर बनकर जिंदगी लीलता रहेगा। साल दर साल सर्दी के मौसम में कोहरे की धुंध की वजह से होने वाले हादसों के लिए हम क्यों अभिशप्त हैं?

आखिर इन दुर्घटनाओं को टालने की गंभीर कोशिश सरकार, समाज व वाहन चालकों की तरफ से क्यों नहीं की जाती? देश की सरकार रोजाना सौ किलोमीटर सड़क का निर्माण करती है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे पर यात्रियों के जानमाल की रक्षा के लिए धुंध से मुक्ति की तकनीक क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? निश्चय ही प्रकृति की लीला का मुकाबला कर पाना संभव नहीं, लेकिन कमोबेश दुर्घटनाओं की संख्या कम करके जान-माल का नुकसान कम करने का प्रयास तो करें। यह सजगता नागरिकों के स्तर पर भी जरूरी है। यात्रा के समय के चयन और धुंध के बीच वाहन चालन में अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस-वे पर पर्याप्त रोशनी और धुंध में दृश्यता बढ़ाने के तकनीकी प्रयास किए जाएं। मौसमी बाधा के बीच दुर्घटना का एक बड़ा कारण राजमार्गों के किनारे अवैध रूप से जगह-जगह खोले गए ढाबे भी बनते हैं। दरअसल, होटल ढाबों के पास वाहनों को अपने परिसर में खड़ा करने की जगह नहीं होती, जिसके चलते ट्रक व अन्य वाहन सड़कों में खड़े रहते हैं। जिसके चलते अक्सर तेजी से आने वाले वाहन दृश्यता की कमी से इन खड़े वाहनों से टकराकर दुर्घटना ग्रस्त हो जाते हैं। पिछले माह राजस्थान के फलोदी के निकट एक टेम्पो ट्रेवलर के सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर से टकराने से दस महिलाओं व चार बच्चों समेत पंद्रह लोगों की मौत हुई थी। इस पर स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। सोमवार को सुनवाई के कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराजगी दिखाई। कोर्ट ने लगातार हादसों की वजह बन रहे इन अवैध होटलों-ढाबों पर नियंत्रण हेतु पूरे देश के लिये दिशा-निर्देश जारी करने की जरूरत बतायी। उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान कोहरा इतना घना हो जाता है कि कुछ मीटर आगे देख पाना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे हालात में थोड़ी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है. इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक विस्तृत ह्यसेफ ट्रैवल इन फॉगह्न एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी का मकसद लोगों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें सचेत करना है ताकि वे सही सावधानियां अपनाकर खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकें। कई अध्ययनों में हादसों की वजह सड़कों के डिजाइन में कमी को भी बताया गया। सवाल है कि जब देश में अच्छी-तेज सड़कों का जाल तीव्र गति से बिछाया जा रहा है तो सुरक्षित सफर सुनिश्चित करना भी तो नीति-नियंताओं की जवाबदेही बनती है? हादसों के लिए सिर्फ चालकों को जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता। हां, इतना जरूर है कि वाहन चालकों को गति के साथ गति भी तेज रखनी होगी। यातायात नियमों का पालन करने में एक जिम्मेदार नागरिक का भी दायित्व निभाना होगा। अगर किसी कारणवश कोहरे में सफर करना बेहद जरूरी हो जाए तो वाहन बेहद धीमी गति से चलाना चाहिए. इसके साथ ही वाहन को पूरी सतर्कता के साथ चलाने की जरूरत है. विशेष रूप से वाहन के म्यूजिक सिस्टम और एफएम रेडियो बंद रखें क्योंकि कोहरे के वक्त सुनने की क्षमता देखने से भी ज्यादा अहम हो जाती है. सामने या पीछे से आने वाले वाहन की आवाज, हॉर्न या किसी आपात स्थिति की ध्वनि समय पर सुनना हदसा टालने में मदद कर सकता है। कोहरे के दौरान वाहन के शीशों पर नमी जमना एक आम समस्या है. इससे सामने का दृश्य और धुंधला हो जाता है. वाहन चलाते समय एयर कंडीशनर के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि इससे कांच पर नमी जम सकती है. इसके बजाय हल्के हीटर का उपयोग करें और हवा का प्रवाह विंडशील्ड की ओर रखें. जिन वाहनों में डिफॉगर की सुविधा है, उन्हें हल्के गर्म मोड पर चालू रखना फायदेमंद होता है. इसके साथ ही वाहन की खिड़कियां थोड़ी खुली रखने की सलाह दी गई है। कोहरे में वाहन की लाइट्स आपकी पहचान बन जाती हैं. एडवाइजरी में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि हेडलाइट्स हमेशा लो बीम पर रखें, क्योंकि हाई बीम कोहरे में रिफ्लेक्ट होकर आंखों को और भ्रमित कर देती है. दिन के समय भी अगर कोहरा बना हुआ है, तो लाइट्स जलाकर चलना जरूरी है. कोहरे में सबसे खतरनाक गलती ओवरटेक करने की होती है. प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे मौसम में ओवरटेक करने से बचना चाहिए. आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अचानक ब्रेक लगाने से बचें. ब्रेक हमेशा धीरे-धीरे लगाएं, दो लेन वाली सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलाना चाहिए और सड़क के बाएं किनारे के करीब रहना ज्यादा सुरक्षित होता है. बीच सड़क पर वाहन चलाना जोखिम भरा हो सकता है. अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के तौर पर जिला प्रशासन ने निजी वाहन चालकों से अपने वाहनों के पीछे लाल रंग की रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की अपील की है. यह टेप कोहरे में दूर से ही चमक जाती है, जिससे पीछे से आने वाले वाहन को पहले ही संकेत मिल जाता है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत व्यावसायिक वाहनों के लिए आगे सफेद और पीछे लाल रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाना पहले से अनिवार्य है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर सर्दियों के मौसम के लिए विशेष गति सीमा भी तय की है. फरवरी तक हल्के वाहनों, जैसे कार आदि, के लिए अधिकतम गति सीमा 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है.वाहन चलाते हुए पर्याप्त दूरी बनाए रखें। सही ड्राइविंग आदतें और नियमों का पालन न सिर्फ आपकी जान बचा सकता है, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी सुरक्षित रख सकता है. कोहरा एक प्राकृतिक स्थिति है, जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन समझदारी और सावधानी से इसके खतरों को जरूर कम किया जा सकता है।

हर मर्ज की एक दवा- गोबर और गौ मूत्र

देश में और कुछ की कमी हो, लेकिन बयानवीरों की कोई कमी नहीं है। नेताओं के बयान पढ़ें तो ऐसा लगता है कि देश विश्वगुरु के पद पर चमक रहा है, बल्कि कहिए कि विश्वगुरु ने पूरी दुनिया के कई - कई बार फेरे लगा चुका है। यहां नयी नयी अद्भुत तकनीक का विकास हो रहा है। लोग नाले की गैस से बनी चाय पी रहे हैं। ताली बजाकर असाध्य रोगियों का इलाज कर रहे हैं। यहां तक कि गौ मूत्र के पान और देह में गोबर लपेस कर सांसारिक दुःखों से मुक्ति पा रहे हैं। जिन्हें धर्म का एबीसी नहीं आता, वे फराटें से धर्म - ज्ञान बांट रहे हैं। आर एस एस के कोई होसबाले हैं, उन्हें बोलते हुए कम ही होश रहता है। वैसे भी आर एस एस के नेताओं का बयान पढ़िए तो समझ में नहीं आयेगा कि कौन सा बयान सच्चा है और कौन झूठा। खैर। इधर होसबाले ने फरमाया है कि मुस्लिम नदी की पूजा करें तो क्या हर्ज है? पहली बात तो यह है कि आप कैसे जानते हैं कि मुस्लिम नदियों का सम्मान नहीं करते और दूसरी बात यह है कि आपने पूजा कर किस किस नदी को बचा लिया? गंगा पर खूब बयान दिए जाते हैं। नमामि गंगे योजना भी चल रही है, मगर इस योजना में गंगा की कम नेताओं, अफसरों और ठेकेदारों का कल्याण ज्यादा हुआ है। यहां तक कि गंगा ने अपने कल्याण के लिए गुजरात से एक बेटे को बुला लिया। उसके करोड़ों बेटे उनके किनारे बसे हैं। उनमें से कोई पसंद नहीं आया। ये सब निकम्मे थे तो गुजरात से पकड़ कर लाया, मगर गंगा आज भी थर थर कांप रही है। यहां तक कि गंगा का आरिजनल जल हरिद्वार में ही लूट लिया जाता है। नरौरा तक आते-आते जो जल पानी हो जाता है। आगे जो गंगा बहती है, उसमें पानी या तो नालों के बचते हैं या फिर सहायक नदियों के। पूजा में इतनी ताकत है तो यमुना को बचा लेते या दामोदर की रक्षा कर लेते। पूजा करने या आरती उतारने से नदियां नहीं बची है, न बचेंगी। ढकोसला, पाखंड और ठगी - जहां नस नस में व्याप्त हो, वहां बयान बच सकते हैं, नदियां नहीं। द्रमुक के सांसद सेंथिल कुमार ने बयान दिया है कि भाजपा को गौ- मूत्र राज्यों में सबसे ज्यादा वोट आता है। गौ मूत्र राज्य यानी हिंदी प्रदेश राज्य। सेंथिल कुमार के बयान बहुतों को बुरे लगेंगे, लेकिन आपने इन राज्यों के साथ क्या किया? पाखंड और अंधविश्वास परोस कर लोगों के कान, आंख और मुंह बंद कर दिए।

लोकसभा में जी राम जी बिल पेश-संसद में घमासान मचा

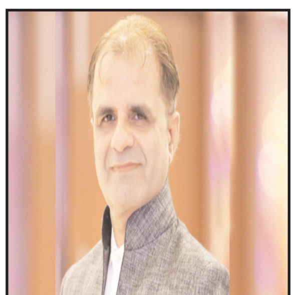

लेखक-किशन सनमुखदास

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था दशकों से संरचनात्मक चुनौतियों, बेरोजगारी अस्थायी आजीविका और कृषि-आधारित जोखिमों से जूझती रही है। वर्ष 2005 में लागू किया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) इन चुनौतियों के विरुद्ध एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप था,जिसने पहली बार ग्रामीण नागरिकों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया। अब संसद में पेश किया गया ह्यविकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी रामजी) बिल न केवल इस कानून को समाप्त करता है, बल्कि ग्रामीण रोजगार की अवधारणा को एक नए वैधानिक ढांचे में पुनर्परिभाषित करने का दावा करता है। यही कारण है कि यह विधेयक नीतिगत से अधिक राजनीतिक, वैचारिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन गया है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यदि हम इसको संवैधानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो,मनरेगा ने अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) और अनुच्छेद 39 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) की भावना को व्यावहारिक रूप दिया था। यदि नया कानून अधिकार आधारित नहीं रहता,तो यह प्रश्न उठेगा कि क्या यह संविधान की सामाजिक न्याय की भावना से पीछे हटना है। यह मुद्दा भविष्य में न्यायिक समीक्षा का विषय भी बन सकता है। साथियों बात अगर हम वीबी-जी रामजी बिल क्या है,एक नया कानूनी ढांचा इसको समझने की करें तो,वीबी-जी रामजी बिल का पूरा नाम विकसित भारतरोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) बिल है। सरकार के अनुसार यह कानून विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को केवल अस्थायी रोजगार नहीं, बल्कि स्थायी आजीविका, कौशल -आधारित रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाना है। इस बिल के तहत ग्रामीण परिवारों को गारंटी वाले काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 करने का प्रस्ताव है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की वार्षिक आय में वृद्धि का दावा किया जा रहा है।मनरेगा को समाप्त कर नया कानून ऐतिहासिक बदलाव, यह बिल संसद में प्रस्तुत होते ही इसलिए विवादों में आ गया क्योंकि यह 2005 के मनरेगा अधिनियम को पूरी तरह समाप्त कर देता है। मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और अधिकार आधारित कानून के रूप में स्थापित रहा है। इसमें काम का अधिकार, समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता, और पारदर्शिता के लिए सामाजिक अंकेक्षण जैसे प्रावधान शामिल थे। वीबी-जी रामजी बिल इन प्रावधानों को किस हद तक बनाए रखता है या बदलता है, यही वर्तमान बहस का केंद्र है।गारंटी वाले कार्यदिवस -100 से 125 दिन का प्रस्ताव,सरकार का कहना है कि 125 दिनों की रोजगार गारंटी ग्रामीण परिवारों को अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। यह कदम विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जहाँ कृषि मौसम पर निर्भरता अधिक है और गैर-कृषि रोजगार के अवसर सीमित हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का तर्क है कि दिनों की संख्या बढ़ाना तभी सार्थक होगा जब भुगतान समय पर हो, काम की गुणवत्ता सुनिश्चित हो और बजटीय आवंटन पर्याप्त हो। राज्यों पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ- वीबी -जी रामजी बिल का एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव यह है कि इसमें राज्य सरकारों की वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। मनरेगा में केंद्र सरकार की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक थी, जबकि नए बिल में राज्यों से अधिक खर्च की अपेक्षा की जा रही है। इससे संघीय ढांचे में असंतुलन की आशंका जताई जा रही है, विशेषकर उन राज्यों में जिनकी वित्तीय स्थिति पहले से ही कमजोर है। रोजगार से आजीविका की ओर नीति का झुकाव-सरकार का दावा है कि यह बिल केवल काम उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधनों को विकसित करेगा। इसके अंतर्गत कौशल विकास,स्थानीयसंसाधनों पर आधारित रोजगार, ग्रामीण उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

कठिन काम

एक लड़का महात्मा के पास पहुंचा। लड़का बड़ा शैतान था, उसको देखते ही महात्मा ने भांप लिया। इसलिए मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रतिबोध देने के लिए महात्मा बोले- बच्चे! तुम तो बड़े तेज दिखाई देते हो। वह अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हुआ और कहने लगा - स्कूल में सब लड़के मुझसे डरते हैं। महात्मा- अच्छा, तुम सरल काम करना चाहते हो या कठिन? लड़का- मैं कठिन से कठिन काम करना चाहता हूं। महात्मा- तुम्हें कोई गाली दे तो तुम क्या करोगे? लड़का- मुझे कोई एक गाली देगा तो उसको दस गाली सुनाऊंगा। महात्मा- ऐसा करना सरल है या कठिन? लड़का- महात्माजी! यह तो मैं बड़ी आसानी से कर लेता हूं। महात्मा- तुम तो तेज लड़के हो, ड्टसा सरल काम क्यों करते हो? लड़का कुछ सकुचाता हुआ बोला- अच्छा, आज से मैं कठिन काम करूंगा। महात्मा- गाली सहना बहुत कठिन है। गाली सुनकर गाली देने वाले बहुत मिलेंगे, पर उस समय खामोश रहने वाले विरले ही होते हैं। लड़का- महात्मा जी! जैसा आपने कहा है, मैं वैसा ही कठिन काम करूंगा। लड़का महात्माजी को वचन देकर आगे चला तो उसे एक दोस्त मिला। उसने एक कंकर उस पर फेंका। वह बालक तिलमिला गया। इतने में उसे महात्मा के शब्द याद आ गए। वह शांत खड़ा रहा। सामने वाला बच्चा यह देखकर दंग रह गया। वह बोला- भैया! मैंने अच्छा नहीं किया, क्षमा करना। ऐसा सुनकर उसने संकल्प कर लिया कि जीवन की स्वस्थता के लिए वह ड्टसे ही काम करेगा।

मोदी-शाह का चेक-मेट: संगठन पर पकड़ भी और बदलाव का भ्रम भी

लेखक- दिलीप कुमार पाठक

बीजेपी अपने निर्णयों से सबको चौका देने के लिए विख्यात है, लेकिन अब बीजेपी अपने दिग्गज नेताओ को किनारे लगाने के लिए भी विख्यात हो गई है, चौकाने के नाम पर मोदी - शाह बड़े पदों पर ऐसी नियुक्तियां कर रहे हैं कि भविष्य में पार्टी की बागडोर उनके हाथों में ही रहे। मोदी - शाह ने पटना की बांकीपुर सीट से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन सिन्हा को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जेपी नड्डा के बाद दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष का कोई औपचारिक पद नहीं है। साल 2019 के बाद से बीजेपी में पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने से पहले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की एक परंपरा शुरू हुई है, कारण सभी को ज्ञात है, मोदी - शाह के निर्णय वही होते हैं कि हमारी मर्जी। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि जब कुछ दिनों बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है तो पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष क्यों नियुक्त किया है? माना जा रहा है कि बीजेपी अपने संविधान के हिसाब से होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को आम सहमति और निर्विरोध रूप से करना चाहती है। बीजेपी जनवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगी, पार्टी में इसकी एक औपचारिक प्रक्रिया है।

ऐसे तो कोई चुनाव नहीं हो रहा है लेकिन नामांकन तिथि, चुनाव तिथि ये औपचारिक प्रक्रियाएं हैं, पार्टी को इन्हें करना है, कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि नितिन नबीन ही अगले अध्यक्ष होंगे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक औपचारिक प्रक्रिया होगी, शायद ही कोई अब पार्टी के भीतर से इस पद के लिए दावेदारी करे, क्योंकि पार्टी में मोदी - शाह से हटकर कोई अपनी बात कहे इतनी भी हैसियत नहीं है, दावेदारी तो फिर भी बड़ी बात है' पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का होता है और अधिकतम एक व्यक्ति लगातार दो कार्यकाल पूरे कर सकता है, नितिन नबीन का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। नितिन नबीन पांच बार से लगातार विधायक हैं और बिहार से बीजेपी के पहले कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 45 साल के नितिन नबीन का कार्यकारी अध्यक्ष बन जाना जरूर कई लोगों को हैरान कर रहा है लेकिन मैं हैरां नहीं हूं क्योंकि बीजेपी अब दिग्गज नेताओं को पद नहीं देगी, जाहिर सी बात है। बिहार चुनावों के दौरान अमित शाह ने नितिन नबीन से दो घंटे मुलाकात की थी, अगर पीछे की कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो नितिन नबीन का नाम बहुत हैरान नहीं करता है, नितिन नबीन पार्टी के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के प्रभारी थे और बीजेपी ने यह चुनाव भारी बहुमत से जीता था। यानी नितिन अपनी संगठनात्मक क्षमता पहले ही साबित कर चुके हैं ऐसे तर्क भाजपा दे सकती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नितिन नबीन की नियुक्ति के पीछे कोई खास वजह या पार्टी की कोई खास रणनीति है? भाजपा पीढ़ी परिवर्तन के नाम पर बड़े - बड़े नेताओ को किनारे कर देती है, अभी अचनाक नबीन को अध्यक्ष बनाना पार्टी में असंतोष बढ़ा देता, इसलिए पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी में उन्हें इसके लिए तैयार कर दिया, तब तक नबीन मीडिया एवं शीर्ष नेतृत्व के साथ अपनी पैठ बना ही लेंगें, ऐसा भाजपा का मानना है क्योंकि किसी दिग्गज नेता को मोदी - शाह अध्यक्ष तो नहीं बनने देंगे कारण स्पष्ट है, नितिन नबीन युवा नेता हैं, मोदी - शाह के दौर में बीजेपी में ऐसे नेताओं को आगे लाया जा रहा है जो किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी या अमित शाह के लिए चुनौती पेश ना करें, नितिन की नियुक्ति हैरान इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें अमित शाह की सहूलियत के हिसाब से बनाया गया है, वे पार्टी के ऐसे कोई मजबूत नेता नहीं है जिनसे अमित शाह को किसी तरह की चुनौती मिल सके। बीजेपी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को इस तरह बना रही है कि मोदी के बाद अमित शाह की ही जगह बने। किसी भी ऐसे नेता को मजबूत पद पर नहीं लाया जा रहा है जो आगे चलकर किसी भी तरह की चुनौती पेश कर पाएं। बीजेपी में इस समय सत्ता मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इर्द-गिर्द ही केंद्रित है और पार्टी के सभी निर्णयों पर इन दो शीर्ष नेताओं की छाप साफ दिखाई दे रही है। पीएम मोदी भी नितिन की नियुक्ति से खुश ही होंगे क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि पार्टी में अमित शाह के लिए कोई चुनौती खड़ी हो, मोदी - शाह संगठन पर पकड़ भी बनाए रखना चाहते हैं और बदलाव का भ्रम भी बनाए रखना चाहते हैं।

प्रसंगतः गुरु का संदेश

छत्रपति शिवाजी ने अपने पराक्रम से अनेक लड़ाइयां जीतीं। इससे उनके मन में थोड़ा अभिमान आ गया। उन्हें लगता था कि उनके जैसा वीर धरती पर और कोई नहीं है। कई बार उनका यह अभिमान औरों के सामने भी झलक पड़ता। एक दिन शिवाजी के महल में उनके गुरु समर्थ रामदास पधारे। शिवाजी वैसे तो रामदास का काफी आदर करते थे लेकिन उनके सामने भी उनका अभिमान व्यक्त हो ही गया, 'गुरुजी अब मैं लाखों लोगों का रक्षक और पालक हूं। मुझे उनके सुख-दुख और भोजन-वस्त्र आदि की काफी चिंता करनी पड़ती है।' रामदास समझ गए कि उनके शिष्य के मन में राजा होने का अभिमान हो गया है। इस अभिमान को तोड़ने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। शाम को शिवाजी के साथ भ्रमण करते हुए रामदास ने अचानक उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखाते हुए कहा, 'शिवा, जरा इस पत्थर को तोड़कर तो देखो।' शिवाजी ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए तत्काल वह पत्थर तोड़ डाला। किंतु यह क्या, पत्थर के बीच से एक जीवित मेंढक एक पतंगे को मुंह में दबाए बैठा था। इसे देखकर शिवाजी चकित रह गए। समर्थ रामदास ने पूछा, 'पत्थर के बीच बैठे इस मेंढक को कौन हवा-पानी दे रहा है? इसका पालक कौन है? कहीं इसके पालन की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर तो नहीं आ पड़ी है?' शिवाजी गुरु की बात का मर्म समझकर लज्जित हो गए। गुरु ने उन्हें समझाया, 'पालक तो सबका एक ही है और वह परम पिता परमेश्वर। हम-तुम तो माध्यम भर हैं। इसलिए उस पर विश्वास रखकर कार्य करो। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी।'

DELHI CRIME dec 2025:Layout 1 12/22/2025 4:21 PM Page 3

दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले 11,776 वाहनों का चालान

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई और तेज कर दी है। बीते 24 घंटों में ही विभिन्न विभागों की टीमों ने प्रदूषण फैलाने और नियमों का पालन न करने वाले कुल 11,776 वाहनों पर चालान जारी किए हैं। यह कार्रवाई शहर भर में समन्वित और सख़्त निगरानी के तहत की गई। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कई स्तरों पर एक साथ काम कर रही है। इसमें वाहनों की जांच, धूल नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और नियमों का सख़्ती से पालन शामिल है। इसी प्रयास का असर है कि इस साल सर्दियों में वायु गुणवत्ता सूचकांक में पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा सुधार देखने को मिला है।

उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ तात्कालिक कदमों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे साल लागू रहने वाली, वैज्ञानिक आधार पर तैयार नीतियों और स्थायी सुधारों पर लगातार काम कर रही है, ताकि दिल्ली की हवा को लंबे समय तक साफ रखा जा सके। शहर की सफाई और धूल नियंत्रण के मोर्चे पर नगर निगम एजेंसियों ने मिलकर 12,164.88 मीट्रिक टन कचरा हटाया। इसके अलावा 2,068.81 किलोमीटर सड़कों की मशीनों से सफाई की गई और 1,830 किलोमीटर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। धूल को नियंत्रित करने के लिए 5,528 किलोमीटर क्षेत्र में एंटी-स्मॉग गन का उपयोग किया गया। निर्माण स्थलों पर लगातार धूल नियंत्रण के लिए 160 एंटी-स्मॉग गन तैनात की गई हैं। कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पिछले 24 घंटों में औसतन 30,000 मीट्रिक टन से अधिक पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया गया। जनता से जुड़े मामलों में भी तेजी दिखाई गई और 311, ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर और सोशल मीडिया के माध्यम से मिली 57 शिकायतों का समाधान किया गया। नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए 542 गैर-निर्धारित मार्गों पर चल रहे ट्रकों को रोका गया और वापस भेजा गया।

साथ ही, शहर के 34 प्रमुख ट्रैफिक जाम वाले स्थानों पर यातायात को सुगम किया गया। सिरसा ने नागरिकों, संस्थानों और वाहन चालकों से प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पूरी तरह पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ यह लड़ाई केवल सरकार की नहीं है। सभी विभाग दिन-रात सतर्क हैं, लेकिन दिल्ली को साफ हवा देने के लिए जनता का सहयोग भी उतना ही जरूरी है।

भारत-ओमान व्यापार समझौते पर होगा तीन महीने में अमल : गोयल

मस्कट। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आशा व्यक्त की कि भारत और ओमान मुक्त व्यापार समझौता अगले तीन महीनों के भीतर लागू हो जाएगा। इससे भारत के श्रम-आधारित निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा तथा फार्मास्युटिकल उत्पाद के लिए के नियामक मंजूरियां भी जल्दी मिल सकेंगीं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देश पहले के व्यापार समझौते में हुई देरी से बचना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "2006 में हस्ताक्षरित हुए ओमान-अमेरिका व्यापार समझौता को लागू होने में लगभग तीन साल लग गए थे। उस अनुभव से सीख लेते हुए भारत और ओमान ने इस समझौते को बहुत तेजी से लागू करने का फैसला किया है।" गोयल ने यह भी कहा कि ओमान डेयरी एवं अमूल डेयरी के बीच एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने को लेकर रुचि दिखाई गयी है। गोयल के अनुसार ओमान ने अपने 98 प्रतिशत से अधिक शुल्कीय मदों में शून्य-शुल्क की पेशकश की है, जो खाड़ी देश को भारत के 99.38 प्रतिशत निर्यात को कवर करती हैं। वर्तमान में, इन उत्पादों पर 5 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक के आयात शुल्क लगते हैं। वहीं भारत ने अपने सकल शुल्कीय मदों में से 77.79 प्रतिशत, या 12,556 उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क छूट की पेशकश की है, जो कुल मिला कर ओमान से भारत के आयात का मूल्य रूप में 94.81 प्रतिशत हैं। ओमान में शून्य शुल्क प्रस्ताव से भारत से आयातित रत्न और आभूषण, वस्त्र, चमड़ा, जूते, खेल के सामान, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग से संबंधित उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण और ऑटोमोबाइल उत्पादों को लाभ होगा। गोयल ने कहा कि ओमान में भारतीय कंपनियों के लिए स्टील, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं हैं, विशेष रूप से संसाधन-सम्बंधित उद्योगों में। उन्होंने पाइपलाइन के क्षेत्र में एक बड़े हरित स्टील प्रोजेक्ट की ओर संकेत किया और ऊर्जा को ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया में परिवर्तित करने में बढ़ती रुचि का भी ज़िक्र किया, जिसे निर्यात के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि ओमान के संप्रभु धन कोष और कंपनियों को भारत में निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया गया था गोयल ने बाद में एक्स पोस्ट पर जारी एक बयान में कहा कि गुरुवार को मस्कट में हस्ताक्षरित हुए भारत-ओमान आर्थिक साझीदारी करार पर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझीदारी समझौता (सीईपीए) व्यापार के नए रास्ते खोलेगा, भारत के निर्यात को बढ़ावा देगा और प्रमुख सेक्टरों में व्यापार के लिए बेहतर अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण एफटीए किए हैं, जिससे विकसित भारत 2047 विजन के तहत वैश्विक व्यापारिक साझीदारियां मजबूत हुई हैं।

प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों का मंत्री इंद्राज ने किया निरीक्षण

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने शुक्रवार को बवाना स्थित वार्ड-30 में स्वच्छता व्यवस्था और प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थलों, नालियों, कूड़ा संग्रहण व्यवस्था का जायजा लेने के बाद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वच्छता बढ़ाने और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा वाहनों से सड़क की सफाई, नियमित पानी का छिड़काव, धूल नियंत्रण, कचरा प्रबंधन को मजबूत करना, खुले में कचरा जलाने पर सख्त कार्रवाई, हरित क्षेत्रों का विस्तार तथा निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कूड़े का समयबद्ध और नियमित उठान सुनिश्चित किया जाए। नालियों की

नियमित सफाई कर जलभराव और गंदगी की समस्या से राहत दें। प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की नियमित जांच कर मानकों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इंद्राज ने आमजन से भी प्रदूषण नियंत्रण में सक्रिय सहयोग की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली का संकल्प, आमजन के सहयोग से ही पूरा होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि खुले में कचरा या अलाव न जलाएं, वाहनों का नियमित प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (पीयूसी) बनवाएं, सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखें और सरकार द्वारा जारी पर्यावरण से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार जनभागीदारी के माध्यम से प्रदूषण-मुक्त, स्वच्छ और स्वस्थ राजधानी की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समाज कल्याण मंत्री ने बवाना गौशाला से शुरू कर, मुख्य मार्ग स्थित पीडब्ल्यूडी ड्रेन, ईश्वर कॉलोनी और विजय नगर में निरीक्षण के दौरान आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, टाटा पावर एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

कांग्रेस ने सरकार पर प्रदूषण के खतरों को नकारने का लगाया आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने संसद के शीतकालीन अधिवेशन को 'प्रदूषण कालीन' सत्र करार देते हुए सरकार पर प्रदूषण के खतरों को नकारने का आरोप लगाया है। शीतकालीन सत्र के शुक्रवार को समापन के बाद जयराम रमेश ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि सत्र की शुरूआत रवींद्रनाथ टैगोर और पंडित नेहरू के बारे में विवादास्पद बयानों से हुई और अब सत्र का समापन महात्मा गांधी के अपमान से हुआ। उन्होंने सरकार पर सदन में इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कल सरकार ने यह बयान दिया कि प्रदूषण और फेफड़ों के बीच कोई संबंध नहीं है। यह बयान चौंकाने वाला है। विभिन्न रिपोर्टों में यह साबित हो चुका है कि प्रदूषण से गंभीर बीमारियां और फेफड़ों के रोग हो रहे हैं लेकिन मोदी सरकार इन तथ्यों को नकार रही है। विपक्ष की ओर से लोकसभा और राज्यसभा में प्रदूषण पर चर्चा की मांग की गई थी लेकिन सरकार ने दोनों सदनों की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। हमने

सोचा था कि आज लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा होगी, जो सरकार ने नहीं कराई। कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि सत्र से पहले एक औपचारिक सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि सरकार 14 विधेयक पेश करेगी, जिनमें से 12 मुख्य होंगे। इनमें से 5 विधेयक पेश नहीं किए गए। रमेश ने कहा, "मैंने 30 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मजाक करते हुए पूछा था कि इस सत्र में कौन सा 'ब्रह्मास्त्र' लाया जाएगा। वह हंसी में जवाब दिए थे लेकिन सत्र में जो हुआ, वह वही था।" उल्लेखनीय है कि पिछले करीब दो महीने से दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है। शुक्रवार को अपराह्न 03 बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 376 दर्ज की गयी, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मानी जाती है।

क्रिसमस प्रेम और करूणा का संदेश देता है : उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली, (हि.स.)। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एकता, प्रेम और करुणा का संदेश देता है। उपराष्ट्रपति ने यह बात उपराष्ट्रपति आवास में 'क्रिसमस लंच' पर कही। उन्होंने सभी को क्रिसमस और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उपराष्ट्रपति ने एक्स पर कहा, "आइए, क्रिसमस जैसे पावन अवसर पर हम एक ऐसे समाज का संकल्प लें जहां हर चेहरे पर मुस्कान और हर दिल में भाईचारा हो। राधाकृष्णन ने बताया कि तरक्की के साथ-साथ पर्यावरण को बचाना भी जरूरी है, इसीलिए उन्होंने 'मिशन लाइफ' की बात की ताकि सभी अपनी आदतों में बदलाव लाकर धरती को सुरक्षित रख सकें और विकास को टिकाऊ

बना सकें। उन्होंने ईसाई समुदाय से राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान जारी रखने का आग्रह किया। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन, राज्यमंत्री सुरेश गोपी और ईसाई समुदाय के वरिष्ठ आध्यात्मिक नेता सहित अन्य चर्च प्रशासनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने एक-दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी और सामूहिक प्रार्थना के साथ देश की समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों और उपस्थित अतिथियों से संवाद किया।

इंडिगो की उड़ानों में गड़बड़ी पर डीजीसीए सख्त, रिपोर्ट आने पर होगी सुधारात्मक कार्रवाई

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में हालिया उड़ान गड़बड़ियों के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। डीजीसीए ने इंडिगो के शीतकालीन कार्यक्रम (शेड्यूल) में 10 फीसदी की कटौती की है। विमानन कंपनी इंडिगो में परिचालन संबंधी व्यापक व्यवधान पर जांच समिति की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद विस्तृत एवं सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीजीसीए की ओर से गठित चार सदस्यीय समिति के जल्द ही रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं कि इस तरह की व्यवधान की

घटनाएं दोबारा न हों। अन्य विमानन कंपनियों के निर्धारित समय पर सेवाएं देने के बारे में बताया गया कि यह साल का वह समय है, जब लोग अधिक यात्रा करते हैं और इस समय कोहरा भी अधिक रहता है। इसलिए विमानन कंपनियों को अधिक उड़ानें संचालित करनी चाहिए। इससे पहले इंडिगो एयरलाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने गुरुवार को कहा था कि विमानन कंपनी अब खुद को मजबूत करने, मूल कारण की समीक्षा करने और फिर से वापसी करने में ध्यान दे रही है।

संसद सत्र बेहद उत्पादक रहा, प्रधानमंत्री के सुधार एजेंडे को भी गति मिली: रिजिजू

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र बेहद उत्पादक रहा और इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुधार के एजेंडे को गति मिली और इसने इस दिशा में अहम भूमिका भी निभाई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद रिजिजू ने पत्रकार वार्ता में कहा कि इस सत्र में पारित विधेयक करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार लाएंगे और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देंगे। इन विधेयकों से देश के करोड़ों लोगों के जीवन में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग शायद इस बात के महत्व को न समझें। रिजिजू ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को लूट

और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया था इसके स्थान पर लाया गया विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी जी राम जी विधेयक से इस स्थिति को ठीक किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि इस सत्र में चुनाव सुधारों पर हुई चर्चा ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। चुनाव प्रक्रिया, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनाव आयोग से जुड़े विषयों को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया। वंदे मातरम पर लंबी चर्चा करके हमने एक बार फिर देशभक्ति की भावना को और आगे बढ़ाया है। संसद के अंतिम दिनों में प्रदूषण पर प्रस्तावित होने के बावजूद चर्चा नहीं होने पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कांग्रेस ने अन्य दलों को उकसाकर सदन नहीं चलने दिया। सरकार इस संबंध में पूरा दिन चर्चा कराने के लिए तैयार थी। संसद के भीतर तृणमूल कांग्रेस सदस्य के ई-सिगरेट पीने से जुड़े प्रश्न पर रिजिजू ने कहा कि सही पाए जाने पर संसद कार्रवाई करेगी। जांच जारी है और फोरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार है।

बंगाल दौरे को लेकर प्रधानमंत्री के ट्वीट पर तृणमूल का पलटवार

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शनिवार को रानाघाट में होने वाली रैली से पहले आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर बंगाल के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया था कि वे शनिवार 20 दिसंबर की दोपहर रानाघाट में भाजपा की रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कुशासन के कारण हर क्षेत्र में पीड़ित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की लूट और धमकी सभी सीमाएं पार कर चुकी है, इसीलिए भाजपा जनता की उम्मीद है। इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार रात अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से मोदी को "मन की बात प्रधानमंत्री" कहते हुए तीखा जवाब दिया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बंगाल के लगभग दो लाख करोड़ रुपये के वाजिब बकाये रोके हुए है, जबकि 2017-18 से 2023-24 के बीच राज्य से साढ़े छह लाख करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी और प्रत्यक्ष कर वसूला गया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी हर मौके पर बंगाल के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सभ्यतागत प्रतीकों का अपमान

मायावती बोलीं- मुस्लिम महिला का हिजाब हटाना दुर्भाग्यपूर्ण, नीतीश कुमार को पश्चाताप करना चाहिए

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाए जाने के विवाद को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मायावती ने कहा कि मुख्यमंत्री को पश्चाताप कर इस प्रकरण को समाप्त कर लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बहराइच पुलिस परेड, विधानसभा और संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बसपा प्रमुख ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण के सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डाक्टर का हिजाब (चेहरे का नकाब) हटाने का मामला सुलझने की बजाय, खासकर मंत्रियों आदि की बयानबाजी के कारण, विवाद का रूप लेकर यह लगातार तूल पकड़ता ही जा रहा है, जो दुखद व दुभाग्यपूर्ण है। यह मामला पहली नजर में ही महिला सुरक्षा व सम्मान से जुड़ा होने के कारण मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप से अब तक सुलझ जाना चाहिये था। खासकर तब जब कई जगहों पर ऐसी अन्य वारदातें भी सुनने को मिल रही हैं। अच्छा होगा कि मुख्यमंत्री इस घटना को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुये इसके लिये पश्चाताप कर लें।

पुलिस परेड के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए – मायावती ने बहराइच में पुलिस परेड के दौरान एक कथावाचक को सलामी दिए जाने के मामले पर भी सवाल उठाए। मायावती ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला पुलिस ने पुलिस परेड में स्थापित नियमों से हटकर, एक कथावाचक को सलामी देने का मामला भी विवाद में हैं। पुलिस परेड व सलामी की अपनी परम्परा, नियम, मयार्दा, अनुशासन व पवित्रता है, जिसको लेकर खिलवाड़ कतई नहीं किया जाना चाहिये। यह अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख ने इस घटना का संज्ञान लेकर जिला पुलिस कप्तान से जवाब तलब किया है।

जनकल्याण के मुद्दों से दूर शीतकालीन सत्र – बसपा प्रमुख ने उप्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र को भी जनहित के मुद्दों से भटका हुआ बताया। उन्होंने कहा कि 19 दिसम्बर से शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के संक्षिप्त शीतकालीन सत्र का सवाल है, तो यह सत्र भी पिछले सत्रों की तरह ही, जनहित व जनकल्याण के मुद्दों से दूर रहने के कारण सत्ता व विपक्ष के बीच वाद-विवाद में घिर गया है।

लोकसेवकों के चयन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को मिले सर्वोच्च प्राथमिकता : राष्ट्रपति

हैदराबाद/नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का कहना है कि लोक सेवा आयोगों को केवल अवसर की समानता के संवैधानिक आदर्श तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि परिणामों की समानता के लक्ष्य को भी हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। लोक सेवा आयोग समानता और न्याय को बढ़ावा देने वाले परिवर्तन के वाहक हैं और उनकी भूमिका देश की शासन व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शुक्रवार को हैदराबाद में लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन करते हुए यह व्यक्त किए। इस सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना लोक सेवा आयोग ने किया था। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा

कि संविधान निमार्ताओं ने सेवाओं और लोक सेवा आयोगों के लिए संविधान में एक पूरा भाग समर्पित किया है, जो इन संस्थाओं के महत्व को रेखांकित करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ-साथ सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता से जुड़े संवैधानिक प्रावधान लोक सेवा आयोगों के कामकाज की दिशा तय करते हैं। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोगों द्वारा चयनित स्थायी कार्यपालिका शासन व्यवस्था को निष्पक्षता, निरंतरता और स्थिरता प्रदान करती है। ऐसे में सिविल सेवकों की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, संवेदनशीलता और दक्षता अत्यंत आवश्यक है। उम्मीदवारों की भर्ती में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि कौशल की कमी को प्रशिक्षण से दूर किया जा सकता है, लेकिन सत्यनिष्ठा की कमी गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकती है। राष्ट्रपति ने कहा कि सिविल सेवा में आने वाले युवाओं में हाशिए पर मौजूद और कमजोर वर्गों के लिए काम करने की भावना होनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति विशेष संवेदनशीलता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि लैंगिक संवेदनशीलता को लोक सेवा आयोगों को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और निकट भविष्य में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रभावी और सक्षम शासन प्रणाली जरूरी है। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि लोक सेवा आयोग भविष्य के लिए तैयार, मूल्यनिष्ठ और सक्षम सिविल सेवकों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे।

DELHI CRIME dec 2025:Layout 1 12/22/2025 4:21 PM Page 4

20 दिसम्बर 2025 को 9 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली क्राइम प्रेस के चमचमाते सितारे अशोक कुमार को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं

गोल घूमती मछली की आंख अर्जुन कभी बेध न पाया होता यदि उसने एकाग्रचित्त हो कर, अपने लक्ष्य सिद्धि हेतु, सतत साधना न की होती। इसी प्रकार गुरूग्राम, हरियाणा के अशोक कुमार ने दिल्ली क्राइम प्रैस के इतिहास में अपना नाम इतनी तेजी से, इतने स्पष्ट अक्षरों में न लिखवाया होता, यदि ये अपने लक्ष्य सिद्धि हेतु इतने क्रियाशील तथा सजग न रहे होते। 20 दिसम्बर 2016 को दिल्ली क्राइम प्रैस के साथ जुड़ने पर, किसी के भी मन में यह विचार नहीं उपजा होगा कि यह सीधा और मासूम सा दिखने वाला लड़का, दिल्ली क्राइम प्रैस में, मात्र 9 वर्ष के अंतराल में, बुलंदियों को छूएगा। ज्वाइनिंग के मात्र 11 दिन बाद पहला प्रमोशन न्यूज सपोर्टर का, जो कि 5 अन्य लोगों को दिल्ली क्राइम प्रैस का पाठक बनवाने पर होता है और मात्र 22 दिन बाद एरिया एडवाइजर बनने पर, सभी का ध्यान अशोक कुमार ने अपनी ओर खींचा था और इस प्रकार दिल्ली क्राइम प्रैस की ओर से न केवल दो प्रमोशनल काड्र्स व उपहार बल्कि प्लान के अनुसार नगद पुरस्कार राशि भी प्राप्त की थी। आपका यह सफर यहीं तक इति श्री नहीं हो गया बल्कि ज्वाइनिंग के मात्र एक माह और 13 दिन की अवधि में जोनल एडवाइजर, 2 माह 28 दिन में डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरऔर मात्र 1 वर्ष 10 दिन के समय अंतराल पर स्टेट एड-वाइजर के सुनहरे रैंक की प्राप्ति भी की। ज्ञात रहे कि जहां पहला प्रमोशन 5 अन्य लोगों के दिल्ली क्राइम प्रैस का पाठक बनने पर होता है तो दूसरा प्रमोशन एरिया एडवाइजर 25 (5+20) पाठक, तीसरा प्रमोशन जोनल एडवाइजर 125 (5+20+100) पाठक, चौथा प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर 625 (5+20+100+500) पाठक तथा पांचवां प्रमोशन स्टेट एडवाइजर 3125 (5+20+100+500+2500) पाठकों के ज्वाइन करने पर होता है और इस संख्या में भी 80:20 का प्रतिशत होना आवश्यक है अर्थात पहले 5 पाठकों में से पहले पाठक के साथ न्यूनतम 20% या अधिकतम 80% तथा बाकी अन्य 4 या अधिक पाठकों के साथ अधिकतम 80% या न्यूनतम 20% पाठकों की सीमा अनिवार्य हो तो मात्र 9 वर्ष के अंतराल में, यह आपके अथक तथा जुझ-ारू प्रवृत्ति का ही परिणाम है कि आज आपकी टीम में 19,000 से अधिक पाठक तथा पत्रकार हैं। इतने कम समय में यह एक श्रेष्ठ उपलब्धि ही मानी जायेगी।

जहां पहले 5 पाठकों के कारण आपने दिल्ली क्राइम प्रैस की डायरी तो उसके बाद के पदोन्नति पर क्रमशः लैपटॉप बैग, मोबाइल फोन, लैपटॉप तथा बाइक उपहा-रस्वरूप ग्रहण किए। दिल्ली क्राइम प्रैस की उच्च मैनेजमेंट ने गुरूग्राम में एक समारोह के आयोजन के साथ आपको बाइक उपहा-रस्वरूप भेंट की, जो निश्चित रूप से आप के तथा दिल्ली क्राइम प्रैस के इतिहास में एक अमिट याद के रूप में अंकित हो गया। अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता अर्थात इतने कम समय में इतनी विशाल पाठकों की फौज खड़ी करना निश्चित रूप से आप के व आप की टीम के प्रयास से ही संभव हो पाया है तथा यह आप के बुद्धि चातुर्य तथा स्वभाव से मिलनसार होने के गुण के कारण ही संभव हो पाया है।

जहां एक ओर अशोक कुमार अपने माध्यम से दिल्ली क्राइम प्रैस में पाठकों की फौज खड़ी करने में व्यस्त थे तो दूसरी ओर मीडिया के विषय में अधिक जानकारी तथा मीडियाकर्मी के रूप में अपनी सीमाओं की जानकारी हेतु आप ने वर्ष 2017 में दिल्ली जर्नलिज्म व इंवेस्टिगेशन रिसर्च इंस्ट-ीट्यूट के प्रथम सत्र में पत्रकारिता का कोर्स उच्चतम ग्रेड के साथ पास किया और दिल्ली क्राइम प्रैस का पत्रकार का कार्ड भी प्राप्त किया और तभी से आप एक सक्रिय पत्रकार के रूप में अपने क्षेत्र में तथा अपनी टीम के साथ मिलकर, उनके क्षेत्र में, जन हित व जन लाभ के परोपकारी कार्यों के लिए भी समय देते रहते हैं। पत्रकारिता के मात्र अपने कोर्स तक सीमित न रहकर आपने अपने साथ अन्य 251 पाठकों को भी पत्रकारिता का कोर्स करवाया, जिस कारण दिल्ली क्राइम प्रैस ने आपको प्रसन्नतापूर्वक ट्राली बैग, लैपटॉप व बाइक के साथ 'वुड केसले टूर' का पारितोषिक भी प्रदान किया। यह आप की परोपकारी प्रवृति ही है, जिसने आप को दिल्ली क्राइम प्रैस के दिल्ली क्राइम व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा नामक रजिस्टर्ड समाजसेवी संस्था (एन. जी. ओ) से जुड़ने के लिए वर्ष 2021 में प्रेरित किया। जहां पहले वर्ष 2022 में आपको 'जन-सम्पर्क अधिकारी' और वर्ष 2023 में गुरूग्राम का 'तहसील हेड' बनाया गया। तब से आप अनगिनत लोगों के घरों की समस्याओं को बिना किसी पारिश्रमिक के, सुलझवा चुके हैं। आप के इस निःस्वार्थ सेवाभाव तथा सहृदय मिलनसार स्वभाव के कारण दिल्ली क्राइम व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा समाजसेवी संस्था ने न केवल गुरूग्राम का 'तहसील हेड' का प्रशस्ति-पत्र दे कर सम्मानित किया बल्कि अधिकारिक रूप से अपनी वेबसाइट पर आप के नाम का उल्लेख भी किया। अपने जन संपर्क के कार्यों तथा गुरूग्राम में दिल्ली क्राइम प्रैस को नयी ऊंचाईयों तक पहुंचाने के अपने दृढ़ संकल्प के कारण, आपने गुरूग्राम में, दिल्ली क्राइम प्रैस का ब्रांच आफिस भी वर्ष 2022 में खोल लिया। जहां से आप अपनी टीम के सदस्यों तथा पत्रकारों को पत्रकारिता तथा नेटवर्किंग के गुरों से परिचित कराते रहने हेतु समय-समय पर मीटिंगों का आयोजन करते रहते हैं। निश्चित रूप से आपकी कार्यशैली, जुनून तथा आपके द्वारा दिल्ली क्राइम प्रैस के हित में किए गये समस्त कार्य, औरों के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं तथा अनुकरणीय हैं। दिल्ली क्राइम प्रैस आपके निष्काम उत्साह व जोश की प्रशंसा करती है तथा आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है।

सदैव अपने पाठकों के लिए पूर्णतया समर्पित
दिल्ली क्राइम व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा

दिल्ली क्राइम के गुरूग्राम ब्रांच आफिस में गीता शुक्ला और इंद्रजीत कौशिक को ड्रा के माध्यम से निकाले गये 'लकी विनर' के रूप में दिल्ली क्राइम के मग उपहारस्वरूप दिए गये।

मेरठ टीम के साथ मुजफ्फरनगर ऑफिस पहुंचे एरिया एडवाइजर शाहिद हसन, संगठन विस्तार की बनाई योजना।

मुजफ्फरनगर जोनल एडवाइजर सत्येंद्र सैनी अपनी टीम के साथ

जीवन रेखा नशा मुक्ति संचालक राहुल सचदेवा को दिल्ली क्राइम प्रेस की सदस्यता दिलाते हुए

मुजफ्फरनगर डीएसओ ने भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेने का दिया आश्वासन।

उत्तराखंड हरिद्वार के कस्बा झबरेड़ा में पूजा सैनी को दिल्ली क्राइम प्रेस की सदस्यता किट देते हुए

दिल्ली क्राइम के गुरूग्राम ब्रांच आफिस में गुड़गांव के संजय गाबा, नोएडा के अतुल, सनी कुमार और छोटू कुमार तथा कैथल के धर्मेन्द्र ढ़ल व गुड़गांव के राजेंद्र को अपना और दिल्ली क्राइम प्रैस का प्रमोशन करने हेतु स्पेशल बैनर देते हुए अशोक कुमार तथा दिनेश शर्मा।

दिल्ली क्राइम परिवार मे आये नए सदस्य परमित सिंह जी को मीडिया एसोसिएट का कार्ड, दिल्ली क्राइम का बैनर, बेच और किट देकर सम्मानित किया

कोटा में राजस्थान टीम लीडर प्रमोद सुमन नए कार्यकर्ता को समाचार पत्र देते हुए।

बिहार जिला छपरा में दिल्ली क्राइम प्रेस के आर एन सिंह द्वारा मीटिंग नंद जी सिंह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बहुत बढ़िया से हुआ है। यहाँ पर जो भी मेंबर आए थे जो भी दिल्ली क्राइम के बारे में और प्लान के बारे बताया गया काफी उत्साहित होकर बड़े ध्यान से सुना। इनका उत्साह दिल्ली क्राइम के प्रति देखने लायक था। इन लोगो द्वारा दिल्ली क्राइम प्रेस के संगठन को आगे बढ़ाने में काफी उत्सुकता दिखा। नंद जी सिंह ने कहा मैंने इसके सहारे कई सामाजिक कार्य किया जो लोगो ने काफी सराहा। इनके बातों को सुनकर सभी लोग काफी उत्साहित दिखे और दिल्ली क्राइम प्रेस के साथ जुड़ने के अपने अपने फॉर्म को भरे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ललित नारायण सिंह सांदू ने अर्जनपुरा गाँव का दौरा किया: विशेष सघन मतदाता सूची सुधार कार्यक्रम के बारे में मार्गदर्शन दिया

दिल्ली क्राइम प्रेस परिवार में रुचि कंवर जी (समाज सेविका) का किया गया स्वागत

दिल्ली क्राइम प्रेस के लीडर एडवोकेट प्रदीप कुमार जी ने अपनी टीम के साथियों हेम लता जी सचिन मितल जी मनोज बंसल जी के साथ सिस्टम की अपडेट और बाकी जानकारी टीम की किट लेते हुए

दिल्ली क्राइम के टीम लीडर और रिपोर्टर राजेंद् कुशवहा जी सतीश कुमार श्रीवास्तव जी किशोरी लाल जैसवाल अपनी टीम के सदस्यों के साथ पश्चिम चम्पारण बिहार मे मीटिंग करते हुए

दिल्ली क्राइम के दो बडे लीडर डॉ आसिफ चौहान और लक्ष्मण जी थाना भवन शामली मे राजकुमार जी के साथ अपनी टीम के साथ मीटिंग करते हुए

दिल्ली क्राइम के शानदार मेहनती लीडर सोहन लाल सैनी जी ने झिंजियाना शामली उतर प्रदेश मे राज कुमार सर के साथ अपनी टीम के लीडर संजय जी, अमित जी, महबूब मिर्जा जी, और डाक्टर साहब के साथ सिस्टम की अपडेट के लिए मीटिंग का आयोजन किया

दिल्ली क्राइम के ग्रेट लीडर सूरत गुजरात से दिलीप कुमार राउत जी जो आजकल दिल्ली मे रहकर दिल्ली क्राइम परिवार मे अपनी टीम को बेहद बढ़िया तरीके से बढ़ाने मे मेहनत कर रहे है

पीतमपुरा, दिल्ली स्थित मुकेश कुमार के आफिस में हुई मीटिंग में अपनी विशेष उपलब्धि पर, 5 दिसंबर को मुकेश कुमार को दो स्पेशल बैनर तथा दिल्ली क्राइम की टाई तथा मालती शर्मा,राहुल व सनी को स्पेशल बैनर द्वारा सम्मानित करते राजकुमार कश्यप तथा अशोक कुमार।

दिल्ली क्राइम की टीम लीडर ज्योति जी, राज कुमार जी के साथ सोनीपत मे टीम लीडर सुशील चौहान जी और उनकी टीम लीडर के साथ मीटिंग को अंजाम देते हुए

राहुल सिंह के द्वारा दिल्ली क्राइम प्रेस की एक शानदार मीटिंग रविवार को घेवरा गाँव मे कि गई,जिसमे दिल्ली क्राइम प्रेस के क्राइम रिपोर्टर और दिल्ली क्राइम एन.जी.ओ के दिल्ली स्टेट हेड अभिषेक कुमार भी मीटिंग मे उपस्थित रहे

दिल्ली क्राइम की टीम ने पचगांव मे मनोज कुमार जी और उनकी वाइफ मीना जी को कार्ड,बैनर,कप और सोहना मे बनवारी लाल जी को दिल्ली क्राइम का कार्ड, बैनर, और कप देकर सम्मानित किया

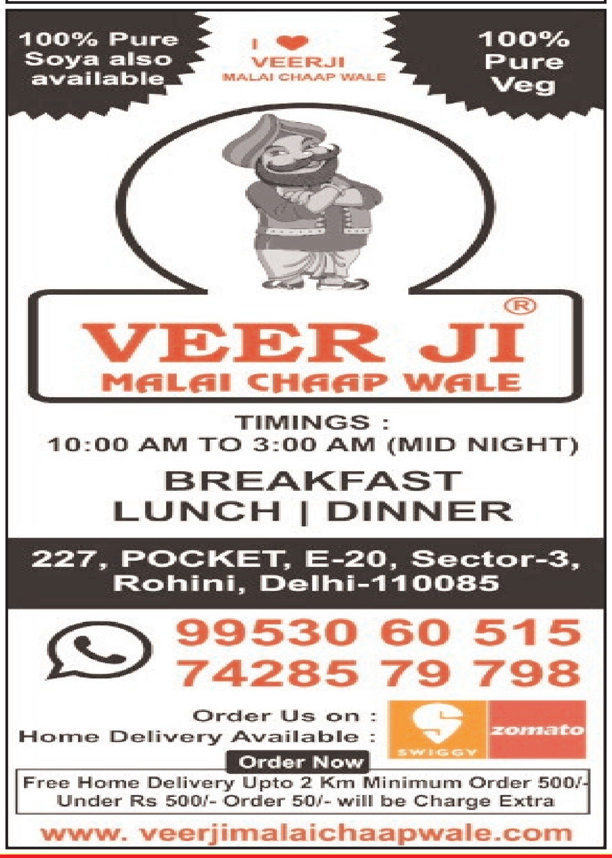

दिल्ली क्राइम के नेशनल लीडर वीरेंद्र कुमार जी जिनके बारे मे यह शेर काफी है की दमखम वही घर घाट वही है शेर अंदर हो या बाहर ठाठ वही है तलवार पुरानी सही मगर काट वही है

हमारे नए अचीवर

राज कुमार कश्यप
डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर

ध्रुव सेठी
डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर

सुशील कुमार
जोनल एडवाइजर

कोमल सैनी
जोनल एडवाइजर

नरेश नेवतिया
न्यूज सपोर्टर

गीता रानी
एरिया एडवाइजर

मोइनुद्दीन
एरिया एडवाइजर

धीरेन्द्र कुमार पांडे
एरिया एडवाइजर

वर्मा राम शंकर हरि राम/ न्यूज सपोर्टर

बलगोविंद सिंह
न्यूज सपोर्टर

सतपाल सिंह
न्यूज सपोर्टर

अमरेंद्र कुमार सिन्हा
न्यूज सपोर्टर

अवनींद्र कुमार
न्यूज सपोर्टर

दिनेश चंद्र यादव
न्यूज सपोर्टर

प्रदीप कुमार पांडे
न्यूज सपोर्टर

राजिंदर कुमार
न्यूज सपोर्टर

मुकेश कुमार
न्यूज सपोर्टर

लव कुमार
न्यूज सपोर्टर

चंदन सिंह
न्यूज सपोर्टर

अभिषेक कुमार पोद्दार
न्यूज सपोर्टर

अभिषेक कुमार
न्यूज सपोर्टर

राजीव
न्यूज सपोर्टर

वीरेंद्र सिंह
न्यूज सपोर्टर

राजराखन गुप्ता
न्यूज सपोर्टर

DELHI CRIME dec 2025:Layout 1 12/22/2025 4:21 PM Page 5

DELHI CRIME dec 2025:Layout 1 12/22/2025 4:21 PM Page 6

गुरूग्राम ब्रांच आफिस में दिल्ली क्राइम प्रैस मीटिंग का सफल आयोजन

रविवार 16 नवंबर को सायं 7 बजे से दिल्ली क्राइम प्रैस के गुरूग्राम ब्रांच आफिस में दिल्ली क्राइम के ठऋड के कर्मठ तहसील हेड तथा सक्रिय प्रैस रिपोर्टर अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली क्राइम प्रैस के पाठकों तथा लीडर्स को पूरी व नयी जानकारियां देना था। इस मीटिंग में शामिल होने वाले पाठक और लीडर्स ही नहीं थे बल्कि नये मेहमानों ने भी इसमें भाग लिया। मीटिंग का शुभारंभ अशोक कुमार ने अपने परिचय के पश्चात उपस्थित लोगों के स्वागत भाषण से किया। तत्पश्चात दिनेश शर्मा ने अपने परिचय के बाद दिल्ली क्राइम प्रैस के माध्यम से मिलने वाले सामाजिक व कानूनी सहायता पर संक्षिप्त प्रकाश डाला तो प्रैस रिपोर्टर पप्पू कुमार ने सभी को दिल्ली क्राइम प्रैस के रिपोर्टर के प्रभाव संबंधित अपने संस्मरण बताए। इंद्रजीत कौशिक ने दिल्ली क्राइम प्रैस के जन हित कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उड़ीसा के तहसील हेड शंभू कुमार ने उड़ीसा में दिल्ली क्राइम प्रैस के वर्चस्व को जोर-शोर से बढ़ाने तथा पूरे देश में डंका बजाने पर जोर दिया। इसी प्रकार अन्य लीडर्स ने अपने-अपने शब्दों में दिल्ली क्राइम प्रैस के प्रति लोगों की रुचि तथा इसके आई कार्ड के माध्यम से मिलने वाले अन्य लाभों से परिचित करवाया। एक बार फिर से अशोक कुमार ने मंच संभालते हुए सभी लोगों को दिल्ली क्राइम प्रैस के तीनों प्लान्स तथा उनके द्वारा होने वाली अतिरिक्त कमाई पर संक्षिप्त प्रकाश डाला, जिसको नये सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सुना तथा अपनी शंकाओं का निवारण करवाया।

मीटिंग के बाद अशोक कुमार ने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार दो लकी ड्रा निकाले। जिसके विजेता इंद्रजीत कौशिक तथा नई मेहमान गीता शुक्ला रही। बाकी सभी सदस्यों को दिल्ली क्राइम का बैज लगाकर व एक पैन दे कर सम्मानित किया गया। दिल्ली क्राइम प्रैस के 'पाठक प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत उत्कृष्ट योगदान देने पर अशोक कुमार तथा दिनेश शर्मा ने नोएडा के सन्नी कुमार,अतुल कुमार और छोटू कुमार तथा गुरूग्राम के धर्मेन्द्र कुमार,राजेन्द्र और संजय गाबा को अपनी ओर से विशेष बैनर दे कर सम्मानित किया। तत्पश्चात सभी सदस्यों को हल्का जलपान दिया गया। सभी सदस्यों की ग्रुप फोटो के साथ ही सफल मीटिंग का समापन कर दिया गया। नोएडा के अतुल कुमार,सन्नी कुमार और छोटू कुमार, दिल्ली से सविता वर्मा, भगवती प्रसाद,लोकेश कुमार तथा मुकेश कुमार ने और गुड़गांव के पप्पू कुमार,शंभू प्रसाद,गीता शुक्ला, राजेन्द्र, धर्मेन्द्र ढ़ल, गिरधारी मिश्र,आविस कुमार, संजय गाबा,राजीव सैदा और मोनू ने भाग लिया।

पीतमपुरा, दिल्ली में दिल्ली क्राइम प्रैस मीटिंग का सफल आयोजन

सूर्य का प्रकाश घटाटोप तिमिर को भी पल भर में छिन्न-भिन्न कर देता है। उपरोक्त कथन की सत्यता की पुष्टि 5 दिसंबर 2025 को शुक्रवार के दिन पीतमपुरा, दिल्ली में हो गयी। ज्ञात रहे कि मुकेश कुमार ने दिल्ली क्राइम प्रैस के साथ जुड़ने के चंद दिन बाद ही अपने माध्यम से 5 लोगों को दिल्ली क्राइम प्रैस के साथ जोड़ दिया और बोनस के रूप में न केवल पैसा अर्जित किया बल्कि अपने पहले प्रमोशन के रूप में News Supporter का नया पद भी ग्रहण किया।

अपनी इस उपलब्धि की खुशी को न छिपाते हुए मुकेश कुमार ने अपने पीतमपुरा, दिल्ली स्थित कार्यालय में दिल्ली क्राइम प्रैस के जाने-माने तथा मुख्य स्तंभ राजकुमार कश्यप तथा गुरूग्राम के सक्रिय पत्रकार व लीडर अशोक कुमार को सादर आमंत्रित किया। इस मीटिंग में सुमित, सनी, पुष्पेंदर, राहुल, लक्ष्मण, रविंदर, मुकेश कुमार,राज कुमार, अशोक, अंजलि, मालती शर्मा, नेहा और दीपिका उपस्थित थे। राजकुमार कश्यप ने उपस्थित लोगों को न केवल दिल्ली क्राइम प्रैस की नीतियों तथा प्लान से परिचित करवाया बल्कि अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किए तो अशोक कुमार ने सरल उदाहरण देते हुए, छोटे-छोटे कदमों की सहायता से, दिल्ली क्राइम प्रैस की ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही अशोक कुमार ने अपनी ओर से मुकेश कुमार को दिल्ली क्राइम प्रैस की टाई तथा दो बैनर भी भेंट किए, जिन के प्रदर्शन से न केवल मुकेश कुमार का अपने क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा बल्कि दिल्ली क्राइम प्रैस के नाम का भी बोलबाला होगा। मीटिंग के समापन पर मुकेश कुमार ने उपस्थित सभी लोगों का मीटिंग में आने के लिए आभार व्यक्त किया तथा दिल्ली क्राइम प्रैस के माध्यम से अपने क्षेत्र में अनेकानेक जन हित के सामाजिक कार्यों को करवाने में रुचि भी दिखाई।

नई मंडी थानाप्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में उपनिरीक्षक संदीप सिंह, उपनिरीक्षक दीपक मावि, कॉस्टेबल रोहित कुमार, कोस्टेबल मुनेश कुमार, कोस्टेबल अभिषेक नागर, कोस्टेबल नरेश कुमार ने सराहनीय गुड वर्क को अंजाम देते हुए मोबाइल चोरी व छिनैती करने वाले गिरोह का पदार्फाश कर लाखों रुपए के मोबाइल भी किये बरामद , मुजफ्फरनगर। एसएसपी संजय कुमार के कुशल मार्ग निर्देशन में नई मंडी थानाप्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा अपनी कार्यशैली के लिए अपनी अलग ही पहचान रखते हैं इनका सदैव यही प्रयास होता है कि पीड़ितों को हर संभव मदद मिले और उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार से मुस्कान लाई जा सके उसके लिए यह सदैव सतत प्रयत्नशील रहते हैं तथा समाज मे पुलिस का इकबाल बुलंद करने में दिन रात लगे रहते है वही समय समय पर अपराधियो के खिलाफ उच्चाधिकारियों के द्वारा चलाये जा रहें अपराध उन्मूलन अभियान में भी अपने अहम भूमिका निभाते है साथ ही बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही हैं तथा शातिर मोबाईल चोर गिरोह की कमर तोड़कर उनके कब्जे से लाखों के मोबिल भी बरामद कर रही है नई मंडी थाना प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा व उनकी टीम अपनी शानदार कार्य शैली से अवगत कराकर दिख रही है कि कोई भी अपराधी या शामिल मोबाइल चोर किसी भी कीमत पर बख्से नहीं जाएंगे ओर आज भी नई मंडी थानाप्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में उपनिरीक्षक संदीप सिंह, उपनिरीक्षक दीपक मावि, कॉस्टेबल रोहित कुमार, कोस्टेबल मुनेश कुमार, कोस्टेबल अभिषेक नागर, कोस्टेबल नरेश कुमार ने सराहनीय गुड वर्क को अंजाम देते हुए मोबाइल चोरी व छिनैती करने वाले गिरोह का पदार्फाश करते हुए 02 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी वे छिनैती के 29 मोबाइल फोन- मुख्यतः एप्पल कम्पनी के आईफोन (अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपये) के बरामद करने में सफलता प्राप्त की है तथा वही अभियुक्तगण चोरी वे छीने गये मोबाइल फोनों को देश के विभिन्न स्थानों व नेपाल-बंगलादेश बेचते थे। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व में भी लगभग आधा-आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है।अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन मेरठ एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के निर्देशन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत, क्षेत्राधिकारी नई मण्डी राजू कुमार साव एव थाना प्रभारी नई मण्डी बृजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

रिपोर्टर सत्येंद्र सैनी

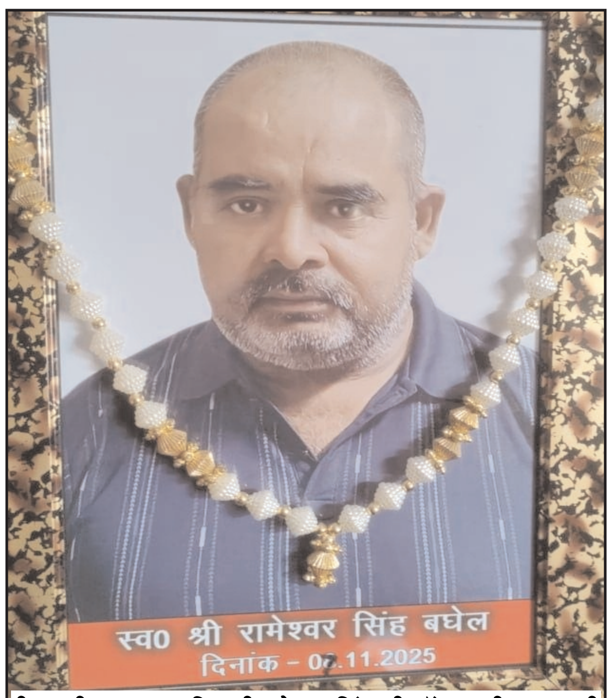

पीलूखनी राया मथुरा निवासी रामेश्वर सिंह की डॉक्टर की लापरवाही से हुई मौत

आंवला रोड बगरैन पर भयानक, सड़क हादसा

आंवला रोड बगरैन स्थित गौरी शंकर इंटर कॉलेज के सामने आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां इंडियन ऑयल के टैंकर ट्रक ने सड़क बुजुर्ग व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

बदायूं, बिसौली से रिपोर्टर एके सोनी

दिल्ली क्राइम प्रेस का बढ़ता हुआ परिवार पूर्व प्रधान राजीव के द्वारा डॉक्टर रविंद्र कुमार को दिल्ली क्राईम प्रेस की सदस्यता दिलाते हुए

चाबी बनाने की कहकर तिजोरी साफ करने वाले दो शातिर चोर पुलिस ने दबोचे।

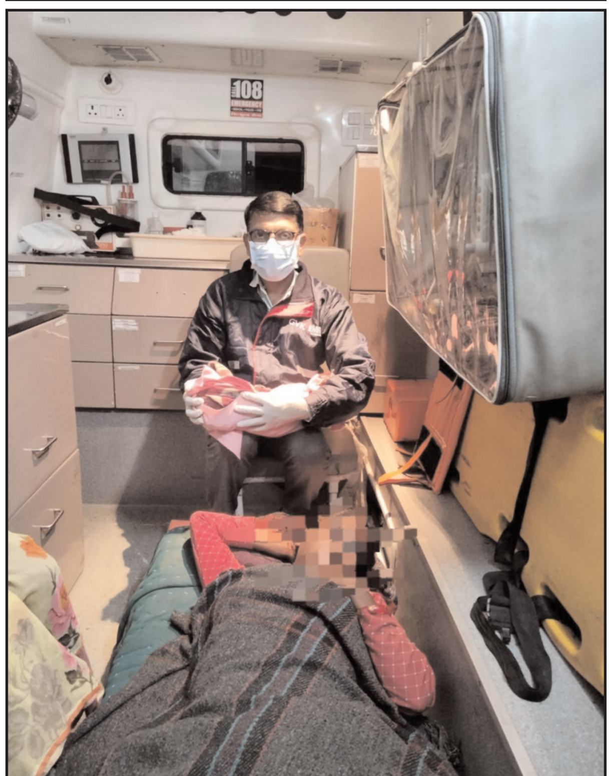

108 टीम की समय पर कार्रवाई से रास्ते में ही सफल प्रसव हुआ - माँ और नवजात स्वस्थ

कुशीनगर पड़रौना में आधुनिक मशीन द्वारा रेत और सीमेंट से ईट बनाने के लिए प्लांट का उद्घाटन

उ प्र कुशीनगर ब्लॉक बिशुनपूरा मे रेत और सीमेंट के द्वारा आधुनिक मशीन से ईट बनाने की मशीन लगाई गई है। यहाँ कुशीनगर मे पहले बार मशीन लगा है, जिसका उद्घाटन भूत पूर्व अध्यक्ष शिव कुमारी द्वारा फीता काट कर किया गया। भट्ठा मालिक वीरेंद्र सिंह का कहना है कि आने वाले समय में सरकार चिमनी के द्वारा होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित कर रही हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए यह मशीन लगा रहे हैं। इससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं है और जिस रेट में भट्ठा का ईट उसी रेट में यह भी दे रहे हैं। इस ईट से एक और फायदे हैं कि मजबूती के साथ साथ दिवाल प्लास्टर नहीं करना पडेगा। मशीन द्वारा 1 घंटे में 1100 ईट बन जाता है। यह प्लांट पड़रौना से 4 किलोमीटर रामकोला मार्ग से सिसवालिया गोदाम से 220 मी उत्तर साइड में है। यह जनपद का पहला प्लांट लगा है। लोगों के उत्साह इस लिए है कि कम कीमत में ज्यादा मजबूत और फायदे ज्यादा है। इस उद्घाटन में कई जाने माने लोग जैसे विशाल सिंह, धनंजय तिवारी, C.P सिंह, राम सूरत सिंह, दिग्विजय प्रधान, जितेंद्र पाठक, जवाहर यादव, मौजूद रहे।

रिपोर्टर राज हुसैन दिल्ली क्राइम प्रेस

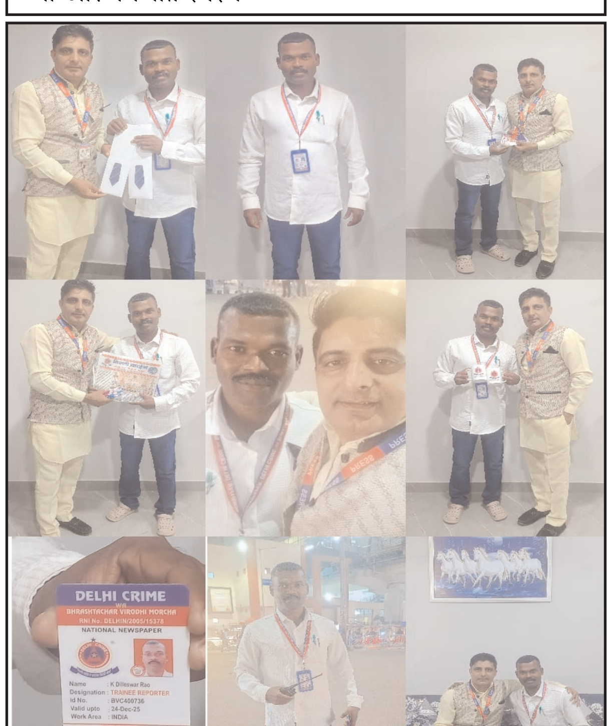

उड़ीसा के सुपर स्टार लीडर और प्रेस रिपोर्टर के दिलेश्वर राव जी को दिल्ली क्राइम की टाई, दिल्ली क्राइम के पेन,दिल्ली क्राइम के मग और न्यूज पेपर देकर सम्मानित किया

जनपद मुजफ्फरनगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील तेवतिया द्वारा मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों का व्यापक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक मोरना स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोकरहेड़ी तथा ब्लॉक पुरकाजी के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शेरपुर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महरायपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेजलहेडा व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरला का दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉ. सुनील तेवतिया ने मेलों में आने वाले मरीजों की पंजीकरण व्यवस्था, ओपीडी सेवाएं, दवा वितरण, जांच सुविधाएं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों से संवाद कर कार्यप्रणाली की जानकारी ली तथा आवश्यक सुधार के निर्देश दिए।

रिपोर्टर सत्येंद्र सैनी

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने शिष्टाचार भेंट की

DELHI CRIME dec 2025:Layout 1 12/22/2025 4:21 PM Page 7

दिल्ली में आबादी देह सर्वे शुरू करेगी सरकार : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से लंबित आबादी देह भूमि की पहचान, स्वामित्व और दस्तावेजी अस्पष्टता को समाप्त करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक एवं दूरगामी पहल की है। अब आबादी देह (गांव की आबादी का क्षेत्र) क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण होगा, उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, साथ ही सत्यापन और कंप्यूटरीकरण भी किया जाएगा। दिल्ली सरकार इस विस्तृत प्रक्रिया को कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के तहत लागू करने जा रही है। यह पहल न केवल भूमि प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाएगी, बल्कि ग्रामीणों को स्वामित्व का वैधानिक प्रमाण और वित्तीय सुरक्षा देने में भी निर्णायक भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सरकार ने ग्रामीण आबादी देह क्षेत्रों में संपत्ति स्वामित्व के अधिकारों को सुनिश्चित करने और दशकों पुराने सीमा विवादों को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शुरू की गई स्वामित्व योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली आबादी देह सर्वेक्षण और अभिलेख संचालन नियमावली, 2025' का मसौदा तैयार कर लिया है। इस सरकारी मसौदे में ड्रोन आधारित हवाई सर्वे, मैदानी सत्यापन, सार्वजनिक आपत्ति प्रक्रिया, विवाद निपटान, डिजिटल रिकॉर्ड और संपत्ति कार्ड जारी करने तक की पूरी कार्यप्रणाली को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो और भूमि से जुड़े विवादों का समाधान पारदर्शी, समयबद्ध और न्यायसंगत तरीके से हो सके। सरकारी प्रावधानों के अनुसार आबादी देह सर्वे की प्रक्रिया राजस्व विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में संचालित की जाएगी। सर्वे टीम और

तकनीकी एजेंसी संयुक्त रूप से गांवों की आबादी देह, विस्तारित आबादी देह, तथा अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए सर्वे कार्य करेंगी। इस प्रक्रिया में ड्रोन और हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से डिजिटल डेटा एकत्र किया जाएगा, जिससे प्रत्येक प्लॉट की सटीक स्थिति, आकार और सीमा को रिकॉर्ड किया जा सके। हालांकि तकनीक आधारित सर्वे के साथ-साथ मैदानी सत्यापन अनिवार्य होगा। ड्रोन सर्वे से तैयार किए गए प्रारंभिक नक्शों का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नक्शे में दर्शाई गई सीमाएं वास्तविक स्थिति से मेल खाती हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राजस्व विभाग ने अप्रैल 2022 में दिल्ली के 48 ग्रामीण गांवों में स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब तक 31 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और 25 गांवों के 'मैप 2.0' की जांच कर उन्हें भारतीय सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया गया है, ताकि जमीन के पार्सल मैप और भू-आधार नंबर जारी किए जा सकें। सर्वे की प्रारंभिक अवस्था में आबादी देह क्षेत्र की सीमाओं को उपयुक्त माध्यम से भौतिक रूप से चिन्हित किया जाएगा। इस दौरान सर्वे टीम द्वारा संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि, निजी प्लॉट, सड़कें, गलियां, नाले, सामुदायिक स्थल, धार्मिक स्थल, कब्रिस्तान, श्मशान, सरकारी संपत्तियां, तथा वे भूमि क्षेत्र जो पेड़ों या संरचनाओं के कारण हवाई सर्वे में स्पष्ट नहीं दिखते, सभी का पृथक-पृथक चिन्हित किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में आवश्यकता पड़ने पर नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), अन्य विभागों और पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा, ताकि सर्वे के दौरान किसी प्रकार की बाधा न आए और सीमाओं से छेड़छाड़ न हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने आबादी देह अभिलेखों के पूर्ण कंप्यूटरीकरण का निर्णय लिया है। इसके तहत राजस्व विभाग द्वारा एक विशेष डिजिटल पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से आम नागरिक शुल्क के भुगतान पर अपने भूमि अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त कर सकेंगे।

इस कदम से न केवल रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि पारदर्शिता और सुगमता भी बढ़ेगी। सर्वेक्षण और अभिलेख संचालन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। यह कार्ड भूमि या संपत्ति के स्वामित्व का वैधानिक प्रमाण होगा, जिससे ग्रामीण नागरिकों को बैंक ऋण, वित्तीय सहायता और विकास योजनाओं का लाभ उठाने में सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से आबादी देह क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। गांवों की विरासत के संरक्षण, नागरिक सुविधाओं के सुधार, भूमि मूल्य में वृद्धि और ग्रामीण ढांचे को शहरी मानकों के अनुरूप विकसित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही सीमाओं और स्वामित्व से जुड़े पुराने विवादों का भी समाधान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे न केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, बल्कि नागरिकों को अपने अधिकारों को लेकर स्पष्टता और सुरक्षा भी मिलेगी। यह प्रक्रिया दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन का नया अध्याय लिखने जा रही है, जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों तक देखा जाएगा।

बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए बनेगा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, अमित शाह ने की समीक्षा बैठक

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में देशभर में बंदरगाहों और जहाजों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक समर्पित निकाय के गठन पर जोर दिया। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी (बीओपएस) के गठन की चर्चा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि बंदरगाहों के सुरक्षा उपायों को जोखिम आधारित और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, जिसमें संवेदनशीलता, व्यापारिक संभावनाओं, भौगोलिक स्थिति और अन्य प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाए। बैठक में बैठक में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भी उपस्थित रहे।

बैठक में ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी को नव-प्रवर्तित मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 2025 की धारा 13 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित करने पर चर्चा हुई। यह ब्यूरो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा और जहाजों तथा बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा से जुड़े नियामक और पर्यवेक्षण कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा। इसका ढांचा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व महानिदेशक करेंगे, जो पे लेवल-15 के आईपीएस अधिकारी होंगे। संक्रमण काल के एक वर्ष के दौरान महानिदेशक शिपिंग (डीजीएस/डीजीएमए) ही ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के महानिदेशक का कार्यभार संभालेंगे। बैठक में यह भी बताया गया कि ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं के समयबद्ध विश्लेषण, संग्रह और आदान-प्रदान को सुनिश्चित करेगा। इसमें साइबर सुरक्षा पर विशेष फोकस रहेगा और बंदरगाहों की आईटी संरचना को डिजिटल खतरों से सुरक्षित रखने के लिए एक समर्पित प्रभाग गठित किया जाएगा। बंदरगाह सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को बंदरगाह सुविधाओं के लिए मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन घोषित किया गया है। सीआईएसएफ बंदरगाहों की सुरक्षा ऑडिट, सुरक्षा योजनाओं की तैयारी और निजी सुरक्षा एजेंसियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की जिम्मेदारी भी निभाएगा। निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि केवल प्रमाणित एजेंसियां ही इस क्षेत्र में कार्य कर सकें। बैठक में बताया गया कि समुद्री सुरक्षा ढांचे से मिले अनुभवों और सबकों को नागरिक उड्डयन सुरक्षा व्यवस्था में भी लागू किया जाएगा।

कर्नाटक विधानसभा में नफरती भाषणों और अपराधों के विरुद्ध कानून की मंजूरी का स्वागत

- देश को नफरत के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना होगाः मौलाना महमूद मदनी

नई दिल्ली। जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कर्नाटक विधानसभा द्वारा घृणास्पद भाषण (हेट स्पीच) और नफरत पर आधारित अपराधों की रोकथाम के लिए कानून की मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बार-बार यह टिप्पणी की है कि देश में नफरत का माहौल बना हुआ है, जो समाज की शांति, भाईचारे और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में कर्नाटक सरकार का यह कदम सामाजिक सद्भाव और भारतीय संविधान में निहित मूल्यों की रक्षा की दिशा में एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण पहल है। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीअत उलमा-ए-हिंद लंबे समय से नफरत फैलाने वाली गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी कानून बनाने की मांग करती आ रही है। इस संबंध में जमीअत ने अदालत के भीतर और बाहर कई स्तरों पर प्रयास किए हैं। नफरत के प्रसार को रोकने के लिए जमीअत ने एक अलग विभाग भी स्थापित किया है। उन्होंने याद दिलाया कि जमीअत उलमा-ए-हिंद की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को तहसीन पूनावाला गाइडलाइंस के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश दिया था। उन्होंने आगे कहा कि अप्रैल 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि घृणास्पद भाषण के विरुद्ध कार्रवाई करना राज्य मशीनरी की संवैधानिक जिम्मेदारी है और इसके लिए किसी औपचारिक शिकायत का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश, अधिकतर राज्यों ने अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ऐसी स्थिति में कर्नाटक सरकार की यह पहल आशा की एक किरण है। मौलाना मदनी ने इस बात पर भी जोर दिया कि नफरत और हिंसा के खिलाफ किसी भी कानून की सफलता केवल उसके अस्तित्व पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इसलिए आवश्यक है कि इस कानून का गहराई से अध्ययन किया जाए और इसकी परिभाषाओं में यदि कोई अस्पष्टता हो तो उसे दूर किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी सरकार इसका दुरुपयोग अल्पसंख्यकों या कमजोर वर्गों के खिलाफ हथियार के रूप में न कर सके।

वायु प्रदूषण दस महीनों में उभरी समस्या नहीं : आशीष सूद

-स्कूलों में 10,000 कक्षाओं में एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे

नई दिल्ली। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी (आआपा) नेताओं के वायु प्रदूषण को लेकर आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने दिल्ली सचिवालय में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि प्रदूषण कोई मौसमी समस्या नहीं है, न ही यह पिछले 10 महीनों में उभरी है। दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं है, यहां का प्रदूषण काफी हद तक पड़ोसी राज्यों से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद कुछ बेरोजगार नेता सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आशीष सूद नें कहा कि यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदूषण को लेकर जमीनी समाधान देने के बजाय केवल विज्ञापन की राजनीति पर ध्यान दिया। कभी ऑड-ईवन, कभी ह्लगाड़ी ऑफह्व जैसे दिखावटी अभियान चलाए गए, जिनका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि विज्ञापनों तक सीमित इन उपायों के बीच नगर निगमों को समय पर फंड नहीं दिए गए, सफाई कर्मचारियों की अनदेखी की गई और स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर व तकनीकी समाधानों पर गंभीरता

से काम नहीं हुआ। आशीष सूद ने कहा कि आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हमारी सरकार सिर्फ. संकल्प नहीं बल्कि लगातार ठोस कार्रवाई कर रही है। स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 10,000 कक्षाओं में एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे। ईवी पालिसी को लागू किया जा रहा है। भलस्वा लैंडफिल को खत्म करने का काम जोरो पर है। नगर निगमों को मजबूत कर सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। सफाई कर्मचारियों के अधिकार, संसाधन और सुरक्षा पर विशेष ध्यान और केवल आपातकालीन उपाय नहीं, बल्कि लॉन्ग-टर्म और स्थायी समाधान पर काम किया जा रहा है। आशीष सूद ने कहा कि अगर आआपा वायु प्रदूषण को कम करना चाहते तो उन्होंने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया होता और आधुनिक मशीनें लगाई होतीं। आआपा ने पिछले 11 सालों में प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दिया। उनके पास विज्ञापनों के लिए पैसा था, लेकिन सार्वजनिक परिवहन के लिए नहीं - यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। आशीष सूद ने कहा कि कुछ बेरोजगार नेता हाल ही में कह रहे थे कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आआपा संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को कम करने के लिए एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका अपनाया था। केजरीवाल ने ऑड-ईवन योजना अपनाई। इस योजना को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने केजरीवाल को फटकार लगाई थी। एनजीटी ने कहा कि आपके पास 100 सुझाव थे, लेकिन आपने हमेशा ऑड-ईवन ही चुना। उन्होंने कहा कि आआपा ने हर समय दिल्ली के प्रदूषण को लेकर केवल राजनीति की है और हमारे सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है।

हमारे सहयोगी संरक्षक एवम् ब्यूरो प्रमुख

प्रधान सम्पादक – नरेन्द्र कुमार

सहयोगी संरक्षक
अनिल सेठी

हमारे स्वतंत्र व सत्यापित रिपोर्टर

- राजकुमार कश्यप (दिल्ली)
- मुकेश गुप्ता (दिल्ली)
- अशोक कुमार (गुरुग्राम)
- राम नरेश (कुशीनगर)
- मो.शरीफ (दिल्ली)
- अभिषेक कुमार (दिल्ली)
- राज हुसैन (कुशीनगर)
- ध्रुव सेठी (पंजाब)
- विक्रमादित्य सिंह (सीधी)
- त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा (सीधी)
- रूप सिंह (दिल्ली)
- सावित्री सिंह (सीधी)
- निखिल सैनी (मुजफ्फरनगर)
- सत्येंद्र सैनी (मुजफ्फरनगर)
- रविकरन सिंह अलीगढ (उ. प्र)

उपरोक्त सभी पद अवैतनिक हैं।

समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री, लेख, रचनाओं, एवम् विज्ञापनों में लेखकों और विज्ञापन दाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए दिल्ली क्राईम व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा की किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही मान्य होगा।

विशेष :- किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने का अधिकार केवल संपादक को है।

61/9 अशोक नगर दिल्ली - 110018

Customer Care No.
8744884766

ADVERTISMENT RATE TARIFF PLAN

FULL PAGE | HALF PAGE | QUARTER PAGE

FULL FRONT PAGE	₹ 1,20,000/-
FULL INNER PAGE	₹ 60,000/-
FULL BACK PAGE	₹ 90,000/-
HALF FRONT PAGE	₹ 66,000/-
HALF PAGE INNER	₹ 36,000/-
HALF PAGE BACK	₹ 51,000/-
QTR. PAGE FRONT	₹ 36,000/-
QTR. PAGE INNER	₹ 21,000/-
QTR. PAGE BACK	₹ 30,000/-

Classifieds Ads. Per Column / 3 CM. Rs.2100/-
Visiting Card Size Advertisements:
Front Page Rs. 6000/- Back Page Rs. 4500/-
Inner Page Rs.3000/-

DELHI CRIME dec 2025:Layout 1 12/22/2025 4:21 PM Page 8

DELHI CRIME WA BHRASHTACHAR VIRODHI MORCHA
दिल्ली क्राईम व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा
RNI:DELHIN/2005/15378
WWW.DELHICRIMEPRESS.IN

2026

Delhi Journalism & Investigation Research Institute
Regd.By Govt Of NCT, Delhi
दिल्ली पत्रकारिता एवं अन्वेषण अनुसंधान संस्थान

JANUARY

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

FEBRUARY

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

MARCH

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

APRIL

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

MAY

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

JUNE

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

JULY

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

AUGUST

S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

SEPTEMBER

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

OCTOBER

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

NOVEMBER

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

DECEMBER

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Helpline No. 7982654944

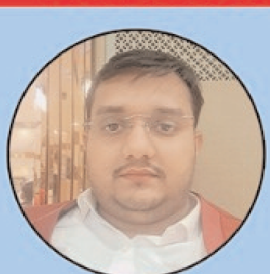

ABHISHEK KUMAR
DELHI STATE HEAD

DELHI CRIME
WA
BHRASHTACHAR VIRODHI MORCHA NATIONAL NGO
भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज़
NITII AAYOG DARPAN REGN. NO. DL/2020/0260865 REGN. NO. S/RS/DW(SW)/1646/2019
C-1/511, NEW YADAV ENCLAVE, PREM NAGAR-3, NEAR CHAUDHARY BALDEV SINGH MODEL SCHOOL,DELHI-110086

DELHI CRIME PRESS की सदस्यता के लाभ

इच्छुक व्यक्ति समाचार पत्र की आजीवन सदस्यता प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं।
सदस्यता लेने के बाद मिलने वाले फायदे।
प्रभावशाली गौरवशाली राष्ट्रीय सेवा को समर्पित रोजगार।
निशुल्क विज्ञापन (एक विजिटिंग कार्ड साइज)।
सदस्यता पहचान पत्र व पेन।
दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के स्टीकर (कार व बाइक के लिए)।
अपने क्षेत्र में अपने राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या पर लेख समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का सुअवसर।
दिल्ली जर्नलिज्म एंड इन्वेस्टिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट (पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्थान) से प्रशिक्षण प्राप्त कर पत्रकार बनने का सुअवसर

स्वामी, प्रकाशक एवम मुद्रक इंद्रा द्वारा रॉयल ऑफसेट, 489 एफ.आई.ई, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली - 110092 से मुद्रित कराकर एम 64, हरी नगर, नई दिल्ली -110064 से प्रकाशित किया गया। संपादक : इंद्रा
Customer Care No. 8744884766, For News & Advertisement 8744882188, Email- info@delhicrimepress.in, website - delhicrimepress.in